A Daily News Magazine

भोपाल

मंगलवार, 14 अप्रैल, 2026

सुबह सवेरे

भोपाल एवं इंदौर से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 23, अंक 221, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

subahsaverenews@gmail.com

facebook.com/subahsaverenews

www.subahsavere.news

twitter.com/subahsaverenews

शरद की सुबह

अपमान का
इतना असर
मत होने दो अपने ऊपर

सदा ही
और सबके आगे
कौन सम्मानित रहा है भू पर

मन से ज्यादा
तुम्हें कोई और नहीं जानता
उसी से पूछकर जानते रहो

उचित-अनुचित
क्या-कुछ
हो जाता है तुमसे

हाथ का काम छोड़कर
बैठ मत जाओ
ऐसे गुम-सुम से।

- भवानी प्रसाद मिश्र

प्रसंगवश

पश्चिम बंगाल चुनाव : मतुआ समुदाय की नाराजी बीजेपी को भारी न पड़ जाए?

प्रभाकर मणि तिवारी

एसआईआर के दौरान मतदाता सूची से नाम कटने के बाद मतुआ समुदाय की नाराज़गी को लेकर बीजेपी के लिए चिंता बढ़ती दिख रही है। क्या यह असंतोष चुनावी नतीजों पर असर डालेगा?

पश्चिम बंगाल में मतुआ समुदाय को बीजेपी का मज़बूत वोट बैंक माना जाता है। इस तबके के समर्थन से ही पार्टी का चुनावी प्रदर्शन लगातार निखरता रहा है। लेकिन अब एसआईआर की कवायद ने बड़ी तादाद में इस समुदाय के लोगों के नाम कट गए हैं। समुदाय के नेताओं का दावा है कि लगभग 70 प्रतिशत मतुआ परिवार इस एसआईआर की प्रक्रिया से प्रभावित हुए हैं। इससे इन लोगों में भारी नाराजगी है।

बीजेपी ने भरोसा दिया था कि नागरिकता कानून के तहत नागरिकता मिलने के बाद उनके नाम मतदाता सूची में बने रहेंगे। लेकिन अब तार्किक विसंगति वाले ऐसे मतदाता कम से कम इस बार तो चुनाव में वोट नहीं दे सकेंगे। राजनीतिक हलकों में सवाल उठ रहा है कि क्या इस तबके की नाराजगी भाजपा को भारी पड़ेगी। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी भी मतुआ-बहुल इलाकों में अपनी रैलियों में यह मुद्दा उठा रही हैं।

मतुआ महासंघ के मुताबिक, राज्य के विभिन्न जिलों में इस समुदाय की आबादी करीब एक करोड़ से ज्यादा है। यह 294 में से कम से कम 45 सीटों पर निर्णायक स्थिति में हैं। खासकर कोलकाता से सटे उत्तर 24-परगना जिले के अलावा नदिया जिले के 20 विधानसभा इलाकों में इनकी अहम मौजूदगी है।

मतुआ समुदाय की शुरुआत 1860 में अविभाजित बंगाल में समाज सुधारक हरिचंद ठाकुर ने की थी। समुदाय के लोग उन्हें भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं और हरिचंद ठाकुर कहते हैं। 1947 में देश के विभाजन के बाद हरिचंद ठाकुर के परिवार वाले सीमा पार कर पश्चिम बंगाल में बस गए। यहां मतुआ समुदाय का जिम्मा हरिचंद ठाकुर के परपोते प्रथम रंजन ठाकुर ने संभाला और उनकी पत्नी वीणापाणि देवी को ही मतुआ माता या बड़ो मां यानी बड़ी मां कहा जाने लगा। बोरो मां ने तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान और बाद में बांग्लादेश से आने वाले इस समुदाय के शरणार्थियों के लिए बांग्लादेश सीमा पर पर ठाकुरनगर नाम से एक बस्ती बसाई। वर्ष 2000 के बाद यह समुदाय एक संगठित वोट बैंक के रूप में उभरा।

हरिचंद ठाकुर के परपोते प्रथम रंजन ठाकुर के दौर से ही परिवार का राजनीतिक रसूख और दखल रहा है। वह 1962 में कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा का चुनाव भी जीते थे। बड़ो मां मतुआ समुदाय के लोगों के लिए बहुत ही सम्मानित थीं। वह खुद तो राजनीति से दूर रहीं। लेकिन 2010 में उनकी ममता बनर्जी से नजदीकियां बढ़ीं और उन्होंने उसी साल दीदी को मतुआ समुदाय का संरक्षक घोषित कर दिया। 2011 के चुनावों में ममता बनर्जी को इसका जबरदस्त फायदा मिला। मतुआ वोटों पर टीएमसी की पकड़ मजबूत हो गई।

2014 में मतुआ माता के बेटे कपिल कृष्ण ठाकुर टीएमसी के टिकट पर लोकसभा पहुंच गए। उनकी मौत के बाद उपचुनाव में टीएमसी ने उनकी पत्नी ममता बाला ठाकुर को टिकट दिया और उन्होंने जीत हासिल की। लेकिन बाद में बीजेपी ने इस वोट बैंक में सेंध लगाई और इसी परिवार के शांतनु ठाकुर को टिकट दिया, जो वर्ष 2019 में जीत कर संसद पहुंचे।

शुरुआत में मतुआ समुदाय का झुकाव वाम दलों की ओर था, लेकिन समय के साथ यह बदलता गया। ममता बनर्जी के उभार के बाद यह समुदाय बड़ी संख्या में तृणमूल कांग्रेस के साथ जुड़ गया। 2011 और 2016 के चुनावों में तृणमूल कांग्रेस को इसका काफी फायदा मिला। लेकिन 2019 लोकसभा और 2021 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने इस वोट बैंक में सेंध लगाई। पीएम मोदी नेतृत्व में बीजेपी ने कई सीटों पर बढ़त बनाई।

भाजपा इस समुदाय को नागरिकता कानून के तहत नागरिकता देने का वादा करती रही है। लेकिन इसकी प्रक्रिया जटिल होने की वजह से अब तक इस समुदाय के ज्यादा लोगों को नागरिकता नहीं मिल सकी है। जरूरी दस्तावेजों के अभाव में अब मतदाता सूची से भी उनके नाम कट गए हैं।

मतुआ नेता और तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा सांसद ममता बाला ठाकुर ने कहा है कि हम लोग तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान से यहां आए थे। केंद्र सरकार ने हमें नागरिकता देने का वादा किया था। लेकिन अब एसआईआर की कवायद ने हमें शरणार्थी से घुसपैठिया बना दिया है।

उत्तर 24-परगना जिले के सीमावर्ती उत्तर पांचपोता गांव में रहने वाली मतुआ आबादी का बड़ा हिस्सा वर्ष 1980 में खुलना (बांग्लादेश) में उत्पीड़न से आजिज आकर यहाँ पहुंचा था। लेकिन इनमें से दर्जनों लोगों के नाम मतदाता सूची से कट गए हैं।

यहां आने के बाद इन सबके पैन कार्ड और वोटर कार्ड बन गए। ज्यादातर लोगों के पास आधार कार्ड भी हैं। लेकिन अब एसआईआर ने इन सबको अधर में लटका दिया है।

इसी गांव के प्रणब मंडल का कहना है कि हमें शुरू से ही भरोसा दिया गया था कि एसआईआर के दौरान किसी हिंदू का नाम नहीं कटेगा। लेकिन हकीकत इसके उलट है। अब हम क्या करें, यह समझ नहीं पा रहे हैं। उनका सवाल है कि कल को केंद्र सरकार हमें घुसपैठिया बता कर बांग्लादेश वापस भेजने का प्रयास करे तो हम कहां जाएंगे।

ममता बनर्जी ने इसी दुखती रग मरहम लगाते हुए कहा है कि बंगाल में कोई डिटेंशन कैंप नहीं खुलेगा और वो यहां से एक व्यक्ति को भी बाहर नहीं भेजने देंगी।

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि मतुआ समुदाय भाजपा का अहम वोट बैंक रहा है। पार्टी उनको नागरिकता देने के वादे करती रही है। नागरिकता कानून भी इसी समुदाय को ध्यान में रखते हुए पारित किया गया था। तब इलाके के लोगों ने बड़े पैमाने पर जश्न मनाया था। लेकिन अब एसआईआर के दौरान बड़े पैमाने पर इस समुदाय के लोगों के नाम कटने की वजह से उनमें भारी नाराजगी है। उनकी यह नाराजगी भाजपा को भारी पड़ सकती है।

(सत्य हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

सड़क हादसों का 'सोमवार'

- तीन हादसों में 24 लोगों की चली गई जान
- महाराष्ट्र में भीषण सड़क हादसा, 11 की मौत

ठाणे (एजेंसी)। महाराष्ट्र के ठाणे में सोमवार को सड़क हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई। दो गंभीर घायल हुए हैं। पुलिस के मुताबिक हादसा सुबह करीब 10.45 बजे मुर्बाड के गोविली गांव स्थित रैता ब्रिज पर हुआ। कल्याण से मुर्बाड जा रही वैन की सामने से आ रहे सीमेंट मिक्सर ट्रक से टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि वैन में सवार 11 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मुर्बाड के तहसीलदार अभिजीत देशमुख ने बताया कि घायलों को उल्हासनगर के सेंट्रल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मरने वालों में 8 पुरुष और 3 महिलाएं हैं। अब तक 6 मृतकों की पहचान हो चुकी है, बाकी की पहचान जारी है। हादसे के बाद कुछ घंटों तक कल्याण से अहिल्यानगर रोड पर लंबा जाम लगा था। कल्याण से मुरबाड के बीच चलती थी वैन वैन रोजाना की तरह आज सुबह भी पैसेंजर्स को लेकर कल्याण से मुरबाड जा रही थी। वैन में ड्राइवर समेत 12-13 लोग सवार थे। इसी दौरान रैता ब्रिज पर सामने से आ रहे सीमेंट मिक्सर से टक्कर हो गई। राहगीरों ने बताया कि दोनों गाड़ियां स्पीड में थीं। टक्कर भीषण थी।

गुजरात में ट्रक ने श्रद्धालुओं को कुचला, 7 की मौत

सुरेंद्रनगर (एजेंसी)। गुजरात के सुरेंद्रनगर में सोमवार सुबह लखतर-विरामगाम नेशनल हाईवे पर एक ट्रक ने पैदल चल रहे श्रद्धालुओं को कुचल दिया। हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि चार घायल हो गए। घायलों को सुरेंद्रनगर के अलग-अलग हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। घायलों की हालत भी गंभीर बनी हुई है। लखतर पुलिस इंस्पेक्टर योगेश पटेल ने बताया कि घटना लखतर-विरामगाम हाईवे पर रात करीब रात करीब 1.30 बजे हुई। तीर्थयात्रियों का एक ग्रुप पैदल राजकोट से बहुचराजी माता मंदिर जा रहा था। तभी पीछे से आ रहे एक ट्रक ने सभी को कुचल दिया। हादसे में छह तीर्थयात्रियों और सड़क किनारे खड़े एक डंपर के ड्राइवर की मौत हो गई। मृतकों में 5 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया था। बाद में इसे गिरफ्तार कर लिया गया। एक श्रद्धालु ने बताया-दत्ता गांव से दर्शन करने के बाद लौट रहे थे।

दूल्हे के पिता समेत 6 बारातियों की मौत

हापुड़ (एजेंसी)। यूपी के हापुड़ में रविवार देर रात 1.30 बजे बारातियों से भरी बस को ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में 5 बारातियों समेत 6 की मौके पर मौत हो गई। 7 गंभीर हैं। बारात गाजियाबाद के

डासना से बुलंदशहर के गुलावठी गई थी। बस में कुल 13 बाराती थे। बाकी दूसरी कारों से पीछे आ रहे थे। शादी के बाद वापस लौटते वक्त बस रोड किनारे खड़ी थी। रास्ता काफी सकरा था। इसी दौरान सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने बस को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद रोड की ढलान पर पहले बस पलटी, फिर बेकाबू ट्रक भी उस पर पलट गया। भारी भरकम ट्रक के पलटने पर बस पिचक गई। बस की छत उखड़कर अलग हो गई। बाराती अंदर दब गए। चीख-पुकार मच गई।

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक में लिए महत्वपूर्ण निर्णय

सिंचाई, सड़क और सेहत पर फोकस, यह बड़े फैसले, जो बदल देंगे प्रदेश की सूरत

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक सोमवार को मंत्रालय में सम्पन्न हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा लोक कल्याणकारी और विकास कार्यों के लिए तकरीबन 19,810 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी गई। मंत्रि-परिषद ने लोक निर्माण विभाग, सिंचाई परियोजना, महिला बाल विकास के कार्यों, नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों तथा कृषि विभाग के प्रस्तावों को भी स्वीकृति दी है। मोहन सरकार ने प्रदेश में सिंचाई नेटवर्क, सड़क बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने और जनता को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के लिए खजाना खोल दिया है। कैबिनेट की बैठक में सोमवार को लगभग 20 हजार करोड़ रुपए की भारी-भरकम राशि को मंजूरी दी गई है।

*** 6 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज की मंजूरी,**
***सागर में 286 करोड़ की सिंचाई परियोजना**
***12.44 लाख लीटर पहुंचा दुग्ध प्रोडक्शन**

मंत्रि-परिषद द्वारा सागर जिले की मिडवासा मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण के लिए 286 करोड़ 26 लाख रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई। इस परियोजना से सागर जिले की सागर तहसील के 27 ग्रामों की 7200 हैक्टेयर भूमि की सिंचाई के लिये किसानों को लाभ मिलेगा।मंत्रि-परिषद द्वारा लोक निर्माण के अंतर्गत विभिन्न विकास कार्यों के लिए 10,801 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी गई। इसके अंतर्गत बी.ओ.टी. मार्गों का विकास एवं पर्यवेक्षण के लिए 150 करोड़ रूपये, बी.ओ.टी. परियोजनाओं की समाप्ति पर भुगतान के लिए 765 करोड़ रूपये, एन्यूटी भुगतान के लिए 4,564 करोड़ रूपये और म.प्र. सड़क विकास निगम (एन.डी.बी.) बाह्य वित्त परियोजना के लिए 5,322 करोड़ रूपये की स्वीकृति सहित 16वें वित्त आयोग की अवधि 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक निरंतर रखे जाने की स्वीकृति दी गई है।मंत्रि-परिषद द्वारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत प्रधानमंत्री पोषण शक्ति और मध्याह्न भोजन सहित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के सुचारू संचालन के लिए 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक निरंतरता के लिए 3,553 करोड़ 35 लाख रूपये की स्वीकृति दी गई है।

मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाईजेशन के तहत कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने, ग्रामीण युवाओं के माध्यम से कस्टम हायरिंग केन्द्रों की स्थापना करने, नरवाई प्रबंधन को बढ़ावा देने और प्रदेश के वन पट्टाधारियों के लिए हस्तचलित/ बैलचलित कृषि यंत्रों पर अनुदान उपलब्ध कराने के लिए योजना आगामी 5 वर्षों के निरन्तर संचालन के लिए 2,250 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी गई है। योजना के क्रियान्वयन से फार्म पॉवर उपलब्धता में वृद्धि होगी। कृषि यंत्रों के उपयोग से श्रमिकों पर निर्भरता में कमी आएगी और लागत एवं समय की बचत सहित रोजगार सृजन होगा। इससे वन-पट्टाधारी कृषक भी लाभान्वित होंगे। मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश में भारत सरकार की सहायता से नए चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना की योजना को आगामी 5 वर्षों तक चलाए जाने के लिए 1,674 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी गई।

10 बड़े और निर्णायक फैसले

- सागर की मिडवासा मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए 286.26 करोड़ रुपये मंजूर
- सड़कों के विकास और रखरखाव के लिए 10,801 करोड़ रुपए स्वीकृत
- सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाईजेशन के तहत 2,250 करोड़ रुपए मंजूर
- नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए 1,674 करोड़ रुपए की स्वीकृति।
- पोषण शक्ति—मध्याह्न भोजन योजना के लिए 3,55 करोड़ रुपये का बजट
- भोपाल गैस पीड़ित स्वास्थ्य सेवाएं के लिए 1,005 करोड़ रुपए का अनुमोदन
- बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ महिला हेल्पलाइन-181 के लिए 240.42 करोड़ रुपए
- मैहर, मऊगंज, पांढुर्णा, धार, इंदौर और झाबुआ जिलों में नए केंद्र खुलेंगे
- नरवाई प्रबंधन के लिए आधुनिक मशीनों पर सब्सिडी का प्रावधान
- कैबिनेट ने लोक कल्याणकारी योजनाओं को 2031 तक निरंतर चलाने लगाई मुहर

बंगाल में भय का हिसाब भरोसे से चुकता करेगी जनता

- बीरभूम की रैली में बोले अमित शाह, ममता सरकार को घेरा
- भाजपा घुसपैठियों को बाहर निकालेगी, भ्रष्टाचार का हिसाब लेगी

कोलकाता (एजेंसी)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को ममता बनर्जी सरकार पर हमले तेज करते हुए कहा कि बंगाल की जनता चुनाव में बम का जवाब बैलेट और भय का जवाब भरोसे से देने वाली है। बीरभूम जिले के मयूरेश्वर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने दावा किया कि पांच मई को बंगाल में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। ममता बनर्जी पर सिंडिकेट स्थापित करने का आरोप लगाते हुए गृह मंत्री ने समाप्त करने का वादा किया।

- **चार मई के बाद विकास का नया दौर शुरू होगा**- गृह मंत्री ने कहा कि चार मई के बाद बंगाल में भय की जगह विकास का नया दौर शुरू होगा। शाह ने कहा कि टीएमसी ने बीरभूम की धरती को बम व बारूद का ढेर बना दिया है। भ्रष्टाचार व गुंडागर्दी में बीरभूम से ज्यादा अनुभव किसको होगा। टीएमसी वालों ने हमारे कार्यकर्ताओं को बहुत परेशान किया है। गृह मंत्री ने चुनाव में हिंसा फैलाने की मंशा रखने वालों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि 23 व 29 अप्रैल को मतदान के दिन अपने घरों में ही बंद रहना।

नोएडा में हिंसक प्रदर्शन, 50 फैक्ट्रियों में तोड़फोड़

- कर्मचारियों ने 10 गाड़ियां फूंकी, जमकर किया पथराव
- सीएम योगी बोले-अशांति फैलाने वालों से सावधान रहें

नोएडा (एजेंसी)। नोएडा में सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे फैक्ट्री कर्मचारियों का प्रदर्शन सोमवार सुबह हिंसक हो गया। अलग-अलग इलाकों में गुस्साए कर्मचारियों ने 50 से ज्यादा फैक्ट्रियों में पथराव किया। तोड़फोड़ की। हाथ में डंडे लेकर सैकड़ों पर कर्मचारी जुलूस निकाल रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक मांगें नहीं मानी जातीं, वो रुकेंगे नहीं। सबसे पहले हालात फेज-2 इलाके में खराब हुए। सुनवाई न होने से कर्मचारी उग्र हो गए। पथराव कर दिया। कई गाड़ियों और बसों को आग लगा दी। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो उनकी गाड़ी पलट दी। हालात बिगड़े तो कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची। कर्मचारियों ने उन पर पथराव कर दिया। फिर पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। सभी रास्तों पर बैरिकेडिंग कर दी। फेज-2 के बाद धीरे-धीरे प्रदर्शन नोएडा के करीब 10 इंडस्ट्रियल इलाकों और आसपास के जिलों में फैल गया। कर्मचारियों ने 30 से ज्यादा फैक्ट्रियों और दफ्तरों में तोड़फोड़ की।

अफवाहों पर ध्यान न देने और शांति बनाए रखने की अपील

प्रशासन कर्मचारियों से अफवाहों पर ध्यान न देने और शांति बनाए रखने की अपील कर रहा है। कर्मचारियों को समझाने की कोशिशें की जा रही हैं। नोएडा डीएम मेधा रुपम ने कहा- अफवाहों पर ध्यान न दें। कंपनियों के साथ बैठक में अहम फैसले लिए गए हैं। वर्कप्लेस पर यौन उत्पीड़न रोकथाम समिति गठित की जाएगी। इसकी अध्यक्ष महिला ही होगी। शिकायत पेटियां रखी जाएंगी। कर्मचारियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाएगा। हर महीने की 10 तारीख तक वेतन का एक मुश्त भुगतान कर दिया जाएगा। वेतन पर्ची अनिवार्य रूप से दी जाएगी।

भोपाल का तापमान
अधिकतम 20°c न्यूनतम 18°c

2

सुबह सवेरे

भोपाल ■ मंगलवार, 14 अप्रैल 2026

जो अग्नि हमें गर्मी देती है, हमें नष्ट भी कर सकती है; यह अग्नि का दोष नहीं है।
चाणक्य नीति

नीतू तिवारी
(मनोविज्ञानी एवं सामाजिक कार्यकर्ता भोपाल)

नारी शक्ति वंदन अधिनियम से मैं भी कर सकती हूँ, की भावना सशक्त होगी

नारी शक्ति वंदन अधिनियम (महिला आरक्षण विधेयक) केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह भारतीय समाज की संरचना में एक गहरा बदलाव लाने वाला कदम है। इसके वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक पहलुओं को हम इस प्रकार देख सकते हैं-

वैज्ञानिक एवं तार्किक पहलू

यद्यपि यह एक कानूनी अधिनियम है, जब निर्णय लेने के लिए महिलाएँ अक्सर समस्याओं को देखने का एक अलग दृष्टिकोण लाती हैं, जिससे नीति निर्माण अधिक सटीक और व्यापक बनता है। महिला प्रतिनिधि बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में निवेश को प्राथमिकता देती हैं, जो सीधे तौर पर मानव विकास को प्रभावित करता है।

दक्षता और नवाचार- लैंगिक समावेशिता किसी भी तंत्र की कार्यक्षमता को बढ़ाती है। जब आबादी के 50 प्रतिशत हिस्से को नीति निर्माण में सक्रिय भागीदारी मिलती है, तो देश की बौद्धिक पूंजी का पूर्ण उपयोग होता है।

मनोवैज्ञानिक पहलू

इसका समाज और महिलाओं के मानस पर गहरा प्रभाव पड़ता है- रोल मॉडल जब युवा लड़कियाँ महिलाओं को सत्ता के शीर्ष पदों पर निर्णय लेते हुए देखेंगी, तो उनके भीतर 'आत्म-प्रभावकारिता' बढ़ेगी। यह 'मैं भी कर सकती हूँ' की भावना को जन्म देता है।

रूढ़िवादिता का टूटना मनोवैज्ञानिक रूप से यह अधिनियम समाज के इस गहरे विश्वास को चुनौती देता है कि 'नेतृत्व केवल पुरुषों का गुण है।' यह सामूहिक अवचेतन नेतृत्व की परिभाषा को बदल देगा।

सशक्तिकरण बनाम प्रतीकात्मकता- यह महिलाओं में सुरक्षा और आत्मविश्वास की भावना पैदा करता है। जब उन्हें पता होता है कि कानून बनाने की प्रक्रिया में उनकी अपनी आवाज शामिल है, तो तंत्र के प्रति उनका भरोसा बढाता है।

भविष्य में समाज पर प्रभाव

आने वाले समय में इसके दूरगामी परिणाम होंगेः नीतिगत प्राथमिकताओं में बदलावः भविष्य में कानून केवल विकास पर केंद्रित न होकर 'संवेदनशील विकास' पर केंद्रित होंगे। स्वास्थ्य, पोषण, और बच्चों की शिक्षा जैसे विषयों पर अधिक बजट और ध्यान केंद्रित होने की संभावना है।

अपराध दर में कमी और संवेदनशीलता- पुलिस और न्याय प्रणाली में महिलाओं की बढाती भागीदारी और संसद में उनके द्वारा बनाए गए कानून, महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों के प्रति समाज का नजरिया बदलेंगे।

आर्थिक सशक्तिकरण- राजनीतिक शक्ति अक्सर आर्थिक अवसरों के द्वार खोलती है। इससे श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, जिससे देश की तष्ठक्कमें उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

पारिवारिक संरचना में बदलाव- घर के भीतर भी सत्ता का संतुलन बदलेगा। जब समाज में महिला की स्थिति 'निर्णायक' की होगी, तो परिवार के भीतर भी उनके सुझावों और निर्णयों को अधिक सम्मान मिलेगा।

निष्कर्ष-नारी शक्ति वंदन अधिनियम भारत के लिए एक (वैचारिक परिवर्तन) की तरह है। यह केवल सीटों का आरक्षण नहीं है, बल्कि भारत के भविष्य को अधिक समावेशी, संवेदनशील और वैज्ञानिक रूप से संतुलित बनाने की एक नींव है। यह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसा वातावरण तैयार करेगा यहां योग्यता लिंग की मोहताज नहीं होगी। मेरे ये विचार संकेत मात्र है हम इसके विस्तार में जितना जाएंगे भविष्य में उतनी ही नई परिभाषा कर पाएंगे कुल मिलाकर भारतीय संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम या सीधी सरल भाषा में कहे तो हर क्षेत्र में आदि आबादी की भागीदारी से देश का विकास और समृद्धि का यह अभियान नए सोपान लिखेगा और भविष्य के समाज को सशक्त करेगा यहां लिंग भेद जैसी कुरीतियों का कोई स्थान नहीं होगा और सभी बराबरी से अपने हक और जिम्मेदारी दोनों का कुशलता पूर्वक निर्वहन कर सकेंगे।

संक्षिप्त समाचार

किसके माथे बिहार का राजपाट! आज होगा तय

● शिवराज की 'पर्ची' से पहले होमवर्क पूरा करने में जुटे दिग्गज

पटना (एजेंसी)। किसके माथे पर बिहार राजपाट लिखा है। शिवराज की पर्ची में किसका नाम है। सियासी गलियारे में ये दो सवाल तैर रहे हैं। बिहार में सत्ता के समीकरण पूरी तरह बदल चुके हैं। नीतिश कुमार के सीएम पद छोड़ने के बाद अब राज्य की कमान भारतीय जनता पार्टी के हाथों में आने वाली है। केंद्रीय नेतृत्व ने दिग्गज नेता शिवराज सिंह चौहान को पर्यवेक्षक तौर नियुक्त किया है। पटना में मंगलवार को भाजपा विधायकों की बैठक में नए मुख्यमंत्री के नाम की औपचारिक घोषणा करेंगे। ये बिहार के इतिहास में पहली बार होगा जब

भाजपा के नेतृत्व में एनडीए सरकार का गठन होगा। इस बड़े बदलाव को लेकर राजधानी पटना में बैठकों का दौर जारी है और सुरक्षा से लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी गई हैं।

शिवराज सिंह चौहान करेंगे नए नेता का ऐलान- मंगलवार को पटना में भाजपा विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। बताया जा रहा है कि दोपहर दो बजे के बाद केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान इस बैठक में पर्यवेक्षक की भूमिका में मौजूद होंगे। बंद लिफाफे से उस नाम का खुलासा करेंगे जो बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनेगा। पार्टी सूत्रों के अनुसार भाजपा का नेता ही एनडीए विधायक दल का नेतृत्व करेगा, जिसके बाद राजभवन में सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। सरकार गठन की कवायद के बीच पटना में उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का आवास सत्ता का केंद्र बना हुआ है। सोमवार को यहां एनडीए के सीनियर नेताओं की मैराथन बैठकें हुईं। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने करीब 40 मिनट तक साझा रणनीति पर चर्चा की। इसके बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी भी गठबंधन की बारीकियों को सुलझाने के लिए वहां पहुंचे।

चुनावों के शोर में हम आंखें नहीं मूंद सकते हैं: एससी

● बंगाल एसआईआर मामले में एससी की चुनाव आयोग पर सख्त टिप्पणी

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पश्चिम बंगाल में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण मामले की सुनवाई की। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव नतीजों में तब तक दखल नहीं दिया जा सकता, जब तक कि जीत का अंतर, सूची से बाहर किए गए वोटों की संख्या से कम न हो। जस्टिस जॉयमाल्य बागची और सीजेआई सूर्यकांत की पीठ ने सुनवाई के दौरान भारत निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि बंगाल के मतदाता अलग-अलग संवैधानिक संस्थाओं के बीच पिस रहे हैं। दरअसल, जस्टिस बागची ने यह टिप्पणी तब की जब चुनाव आयोग ने दलील दी

कि न्यायिक अधिकारियों ने तार्किक विसंगति के 47 फीसदी मामलों को खारिज कर दिया है, ये वे अधिकारी थे जिन्होंने चुनाव आयोग द्वारा जारी नोटिसों पर फैसला सुनाया था। कोर्ट ने यह टिप्पणी भी की कि चुनाव आयोग ने ही पश्चिम बंगाल में एसआईआर के दौरान संदिग्ध मतदाताओं की एक तार्किक विसंगति सूची बनाई थी। जिसके जवाब में जस्टिस बागची ने कहा, यहां बात यह नहीं है कि साध्य साधनों को सही ठहराता है, बल्कि यह है कि साधन साध्य को सही ठहराते हैं। यह राज्य सरकार और चुनाव आयोग के बीच की लड़ाई नहीं है। यह कोई एक-दूसरे पर दोष मढ़ने का खेल (ब्लेम गेम) भी नहीं है। यह तो मतदाताओं के दो संवैधानिक संस्थाओं के बीच पिसने का मामला है। अदालतों ने केवल चुनावों को बढ़ावा देने के लिए हस्तक्षेप किया है, न कि उनमें रुकावट डालने के लिए।

खुशखबरी! 20,400 टन एलपीजी आज पहुंचेगी भारत

होर्मुज से निकला जग विक्रम, संकट के बीच बड़ी राहत

नई दिल्ली (एजेंसी)। सरकार ने एलपीजी जहाज जग विक्रम पर बड़ा अपडेट दिया है। इसके कल 14 अप्रैल यानी मंगलवार को कांडला (गुजरात) पहुंचने की उम्मीद है। इस पर 20,400 टन एलपीजी लदी है। इसमें 24 नाविक सवार हैं। यह जहाज 11 अप्रैल को होर्मुज स्ट्रेट से गुजरा था।

संकट के बीच यह बड़ी राहत की खबर है। बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव मुकेश मंगल ने सोमवार को इस बारे में पूरी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारतीय ध्वज वाला एलपीजी जहाज 'जग विक्रम' 11 अप्रैल को होर्मुज स्ट्रेट से गुजरा।

इस जहाज पर लगभग 20,400 टन एलपीजी लदी है। इसमें 24 नाविक सवार हैं। इसके 14 अप्रैल को कांडला पहुंचने की उम्मीद है। इसके साथ ही मुकेश मंगल ने यह भी कहा कि भारत के सभी बंदरगाहों पर कामकाज सामान्य रूप से चल रहा है। किसी भी तरह की भीड़भाड़ (कंजेशन) की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

● **सीजफायर के बाद होर्मुज पार करने वाला पहला भारतीय जहाज-** अमेरिका और ईरान के बीच दो हफ्ते के अस्थायी संघर्ष-विराम की घोषणा के बाद जग विक्रम होर्मुज पार करना वाला पहला भारतीय जहाज था। जग विक्रम मार्च की शुरुआत से अब तक फारस की खाड़ी से बाहर निकलने वाला भारत का नौवां जहाज भी है। भारत अपनी एनर्जी जरूरतों के लिए आयात पर काफी हद तक निर्भर है। लगभग 88 फीसदी कच्चा तेल, करीब आधी नैचुरल गैस और लगभग 60 फीसदी एलपीजी की जरूरत वह इंपोर्ट से पूरी करता है। ज्यादातर सप्लाई खाड़ी देशों से होती है। यह हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर ही गुजरती है।

हरीश पाठक के उपन्यास 'गाँठें' में दो सदियों के राजनीतिक-सामाजिक संघर्ष की दास्तान

भोपाल। हिंदी के सुपरिचित कवि और कथाकार डॉ. हरीश पाठक के नए उपन्यास 'गाँठें' भारत के 200 सालों की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति का अभूतपूर्व चित्रण करता है। इसमें परिवारों की संरचना, दत्तक प्रथा, बहुविवाह एवं बालविवाह से उत्पन्न अन्याय, शोषण और संघर्ष की अनवरत दास्तान है।

हिंदी के पाँच प्रख्यात लेखकों ने इस चर्चित उपन्यास पर बातचीत की और कहा कि उपन्यास बहुत बड़ा है और कुछ ज़्यादा ही विस्तार में बातें कही गई हैं। फिर भी कहना होगा कि यह उपन्यास हिंदी के कथा साहित्य की अनुपम रचना है। इसका आयोजन जनवादी लेखक संघ ने दुष्यंत संग्रहण में किया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता हिंदी के शीर्ष आलोचक और कवि प्रो विजय बहादुर सिंह ने की। उन्होंने कहा कि 1965 से 1967 के दौरान माधव कॉलेज, उज्जैन में हरीश पाठक जब पढ़ते थे, तब मैं शोध कर रहा था। उन्होंने देश, समाज और परिवार के उस वक़्त के घटनाक्रम को बड़ी बारीकी से उकेरा है। प्रख्यात कवयित्री और कथाकार प्रो सविता भार्गव ने चर्चा की शुरुआत करते हुए उपन्यास का कथानक, घटनाओं, पात्रों का विवरण और एक तरह से उपन्यास का पूरा निचोड़ विस्तार से प्रस्तुत किया, जिससे श्रोताओं का उपन्यास से पूर्णतः परिचय हो गया। हिंदी के जानेमाने आलोचक रामप्रकाश त्रिपाठी ने 'गाँठें' के सामाजिक ताने-बाने को रेखांकित करते हुए इसका समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण सामने रखा। सुपरिचित कथाकार शशांक ने उपन्यास के तकनीकी कौशल, कला पक्ष और ख़ासकर इसकी भाषा को विशेष रूप से रेखांकित करते हुए कहा कि यह बेहद उल्लेखनीय है। देश के शीर्ष कवि और कथाकार राजेश जोशी ने कार्यक्रम का संचालन करते हुए हरीश पाठक के साहित्य में योगदान की विशेष रूप से चर्चा की। संघ के प्रदेशाध्यक्ष और प्रख्यात लेखक वीरेंद्र जैन ने आभार माना। इस उपन्यास का लोकार्पण केंद्र सरकार के भाषा साहित्य परिसंवाद में देश भर के विद्वानों ने किया था। अंत में प्रख्यात गायिका आशा भोसले और पत्रकार राजेश बादल की माताजी के स्वर्गवास पर श्रद्धांजलि दी गई।

डिंडोरी में वन अधिकार के लिए प्रदर्शन, समिति बनेगी

डिंडोरी। जिले के 86 वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर आदिवासियों ने प्रदर्शन कर कलेक्टर के नाम एसडीएम को ज्ञापन दिया। इस प्रदर्शन में बैठा समुदाय के वन ग्रामों में बसे करीब पांच हजार लोग शामिल हुए। ज्ञापन के बाद हुई चर्चा में जिला और तहसील स्तर पर महीने में एक बार वन अधिकार समन्वय बैठक हो जिसमे स्थानीय संगठन और विषय विशेषज्ञों से परामर्श की मांग की गई। पिछले वर्ष भी इसे लेकर शांतिपूर्ण धरने और प्रदर्शन हुए हैं। प्रभावित लोगों ने कई बार जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपे हैं। यदि प्रशासन हर बार कि तरह इसे हल्के में लिया जाता है तो तो इस बार संगठित रूप से अनिश्चितकालीन आंदोलन किया जाएगा और जिला प्रशासन की जबावदेही जनता की अदालत में तय की जाएगी। इस मांग के बाद एसडीएम ने ब्लॉक स्तर पर एक समिति बनाने के लिए सहमति दी। इस समिति में प्रशासनिक अधिकारी एवं ग्रामीण प्रतिनिधि शामिल रहेंगे। समिति के माध्यम से प्रत्येक माह नियमित चर्चा आयोजित की जाएगी। सामुदायिक वन संसाधन अधिकार के प्रकरणों में समय लगने की बात कही गई है, क्योंकि वर्तमान में बजट उपलब्ध नहीं है। व्यक्तिगत वन अधिकार के अंतर्गत केवल उन प्रकरणों की समीक्षा की जा रही है, जिन्हें वर्ष 2006 से पहले अधिकार प्राप्त हुआ था-उन्हें कितना अधिकार मिला और किन लोगों के प्रकरण छूट गए हैं। वर्तमान में नए दावे स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं, केवल पूर्व प्रकरणों का ही परीक्षण किया जा रहा है।

आज अम्बेडकर जयंती

बाबा साहेब जन्म स्थली स्मारक महू में होगा विशाल समागम, मुख्यमंत्री विशेष रूप से होंगे शामिल

भोपाल (नप्र)। संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेड़कर की जयंती इंदौर में 14 अप्रैल को पूर्ण आस्था एवं अपार उत्साह के साथ मनाई जाएगी। डॉ. अम्बेड़कर नगर महू में स्थित उनकी जन्मस्थली पर बने भव्य स्मारक में विशाल समागम होगा। श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव विशेष रूप से इस आयोजन में शामिल होंगे।

प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी 14 अप्रैल को डॉ. अम्बेडकर जयंती उत्सव समारोह पूर्ण उत्साह, उमंग और आस्था के साथ इंदौर जिले के डॉ. अंबेडकर नगर (महू) में मनाया जा रहा है। जयंती उत्सव में आने वाले श्रद्धालुओं की मेहमानों की तरह आवभगत की जा रही है। श्रद्धालुओं के लिए आवास, भोजन, शीतल पेयजल आदि की विशेष व्यवस्था की गई है। जन्म स्थली पर बने भव्य स्मारक पर विशेष साज-सज्जा की गई है।

अम्बेडकर जयंती उत्सव समारोह में मध्यप्रदेश सहित अन्य प्रदेशों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। श्रद्धालुओं के आगमन का सिलसिला 12 अप्रैल की शाम से शुरू हो गया है। श्रद्धालुओं के भोजन की व्यवस्था स्वर्ग मंदिर परिसर में की गई। उक्त भोजन व्यवस्था 14 अप्रैल की शाम तक जारी रहेगी। भंतो के भोजन की व्यवस्था माहेश्वरी स्कूल में की गई है तथा उनके रूकने की व्यवस्था भी माहेश्वरी स्कूल में है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिये पर्याप्त संख्या में अस्थाई शौचालयों का निर्माण भी किया गया है। पेयजल व्यवस्था के लिये विभिन्न स्थानों पर प्याऊ का निर्माण किया गया है।अम्बेडकर जयंती के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं के रूकने के लिये धर्मशालाओं, केन्ट बोर्ड हायर सेकेण्डरी स्कूल एवं केन्ट बोर्ड कन्या स्कूल में की गई है। इसके अलावा तीन विशाल डोम भी ठहरने के लिए बनाए गए हैं।

अमेरिका-ईरान संधि वार्ता, लौट के वांस अमेरिका आए

जयंती पर विशेष

डॉ. सुधीर सक्सेना
लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

महाबली अमेरिका और जुझारू ईरान के दरम्यां अम्न-ओ-अमान की वार्ता फैसलाकुन साबित नहीं हुई और 21 घंटों में ही उसने दमतोड़ दिया, फलतः उपराष्ट्रपति जेडी वांस अपने सहयोगियों- कुश्नर और विटकोफ के साथ अमेरिका लौट आये। उन्होंने बेनतीजा वार्ता को अमेरिका के लिये बुरा और ईरान के लिये बहुत बुरा करार दिया, तो यह साफ हो गया कि अमेरिका को शांति की ज्यादा फिक्र नहीं है और उसके मन में ईरान को तबाह करने का मंसूबा सिर उठाये हुये है। इस्लामाबाद में हुयी शांति वार्ता में वांस की शिरकत से तेहरान को बड़ी उम्मीदें थीं। एक तो वह उदार माने जाते हैं, दूसरे अन्होंने 28 फरवरी से पेश्तर हंगरी में अपने बयान में ईरान पर धावे की मुखालफत की थी, लेकिन इस्लामाबाद में उनका रवैया अड़ियल रहा और वह ट्रंप के सुर में बोलते दिखे। यूं भी आंतंकवादी राष्ट्र के फौजी शासक की पहल पर हुई यह वार्ता शुरू से ही आशंका के आवर्त में रही। वार्ता के दरम्यान इस्त्रायल ने दक्षिण लेबनान पर बमबारी जारी रखी और हिजबुल्लाह प्रमुख नईम कासिम को मार गिराने का दावा किया। उसकी बमबारी से शवयात्रा में शरीक लोगों समेत करीब डेढ़ हजार लोग हताहत हुये। इस पर तेहरान की आपत्ति पर तेल अवीव ने ढिठाई से उत्तर दिया कि उसका शांति वार्ता से कोई वास्ता नहीं है। इस बीच

अमेरिका ने अपना विमानवाहक युद्धपोत भी होरमुज की ओर रवाना किया, जिसे ईरान के ऐतराज के बाद डाइवर्ट किया गया। इससे जाहिर है कि इस्त्रायल अपना ग्रेटर इस्त्रायल, जिसमें गाजा, सिनाई, गोलन हाइट्स समेत सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, मिस्त्र आदि के हिस्से शामिल हैं, के मिशन को पूरा करना चाहता है और ट्रंप ईरान को निर्णायक शिकस्त देना चाहते हैं।

तेहरान और वाशिंगटन के बीच झगड़े की जड़ यूरेनियम-संवर्द्धन और होर्मुज जलडमरूमध्य हैं। तेहरान परमाणु बम बनाने का इरादा तो छोड़ सकता है, किंतु परमाणु-संवर्द्धन का मिशन नहीं। ऐसे ही वह होर्मुज स्ट्रेट के हाथ लगे ब्लैंक-चेक को भुनाने का मौका भी नहीं छोड़ना चाहेगा। शांति तभी संभव है, जब दोनों पक्ष घुटना टेकने के बजाय घुटने मोड़ने की नीति पर चलें। यह अकारण नहीं है कि न्यूयार्क के मेयर ममदानी ने जंग पर दसियों अरब डालर फूंकने का विरोध किया है, मगर जिद्दी और खब्ती ट्रंप 'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन' के फेर में ईरान की मुश्कें कसने के लिये कुछ भी कर सकते हैं, लिहाजा शांति की घड़ियां दूर हैं और तबाही सन्निकट।

शराब दुकान के विरोध में भोपाल जिपं उपाध्यक्ष का धरना

हाथों में पोस्टर-तख्तियां लेकर बैठे ईंटखेड़ी में शटर गिराकर धरना

भोपाल (नप्र)। भोपाल में शराब दुकानों की शिफ्टिंग को लेकर विरोध लगातार तेज होता जा रहा है। कोलार रोड, पॉलिटेक्निक चौराहा, अवधपुरी और सेमराकलां के बाद अब ईंटखेड़ी में भी लोग सड़कों पर उतर आए हैं।

ईंटखेड़ी में शराब दुकान के विरोध में जिला पंचायत उपाध्यक्ष मोहन सिंह जाट खुद धरने पर बैठ गए हैं। ग्रामीणों ने पहले दुकान का शटर गिराया, फिर मौके पर टेंट लगाकर भजन-कीर्तन शुरू कर दिया। ग्रामीणों और मोहन सिंह जाट ने कुछ दिन पहले कलेक्टर को आवेदन देकर दुकान हटाने की मांग की थी। लेकिन सोमवार तक कार्रवाई नहीं होने पर दोपहर 12 बजे से दुकान के सामने ही प्रदर्शन शुरू कर दिया गया।

स्कूल-कॉलेज के रास्ते में दुकान, ग्रामीण परेशान

ग्रामीणों का कहना है कि यह शराब दुकान भैंरोपुरा, कल्याणपुरा और खामखेड़ा जाने वाले रास्ते पर है। दुकान के सामने ही लोग बैठकर शराब पीते हैं, जिससे आने-जाने वालों, खासकर महिलाओं और बच्चों को परेशानी होती है।जाट ने कहा कि दुकान के कारण असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है, जिससे क्षेत्र का माहौल खराब हो रहा है।

ठेकेदार और साथी को बस ने कुचला

एक की मौत, बाइक पर सवार होकर साइट देखने निकले थे दोनों

भोपाल (नप्र)। सीहोर के देलावाड़ी में चौहान ट्रैवल्स की बस की चपेट में आने से भोपाल के ठेकेदार की मौत हो गई। उसका एक साथी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। सोमवार को पीएम के बाद बॉडी परिजनों को सौंप दी गई है। कमर मियां, पिता रईस मियां (35), निवासी वार्ड नंबर 6, लाऊखेड़ी एयरपोर्ट रोड पेंटिंग ठेकेदारी करते थे। रविवार की शाम करीब पांच बजे देलावाड़ी घाट के पास चौहान बस ने सामने से जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में कमर व बाइक सवार दूसरे साथी को गंभीर चोट आई। दोनों को भोपाल के हमीदिया अस्पताल लाया गया। जहां इलाज के दौरान सोमवार तड़के कमर की मौत हो गई। साथी गंभीर है, उसका इलाज अस्पताल में जारी है।

साइट देखने बुधनी जा रहे थे दोनों युवक- कमर अपने साथी के साथ प्लेटीना बाइक पर सवार होकर बुधनी जाने के लिए रविवार की दोपहर तीन बजे भोपाल से निकले थे। बुधनी में उन्हें एक साइट देखने जाना था। रास्ते में वह हादसे का शिकार हो गए। वहीं, पुलिस का कहना है कि बस नंबर के आधार पर आरोपी चालक की पहचान की कोशिश की जा रही है।

महिला चरस तस्कर सहित तीन गिरफ्तार

भोपाल में ड्रग्स सिंडिकेट का पर्दाफाश, क्राइम ब्रांच का एक्शन, ड्रायर में छिपाकर रखते थे चरस

भोपाल (नप्र)। भोपाल क्राइम ब्रांच ने रविवार रात बड़ी कार्रवाई करते हुए चरस तस्करी के नेटवर्क का खुलासा किया है। पुलिस ने एमपी नगर जोन-1 क्षेत्र से एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से 126 ग्राम चरस बरामद की।

पकड़े गए आरोपी मंसूर खान (निवासी कोतवाली) ने पूछताछ में बताया कि वह चरस शाहजहांनाबाद की रहने वाली महिला तस्कर से खरीदता था। इसके बाद क्राइम ब्रांच ने आरोपी की निशानदेही पर शाहजहांनाबाद स्थित घर पर दबिश दी।

वॉशिंग मशीन से 7 लाख रुपए कीमत का माल जब्त

छापेमारी के दौरान पुलिस को घर में रखी वॉशिंग मशीन के ड्रायर से करीब डेढ़ किलो चरस बरामद हुआ। इसके बाद महिला नौशीन खान और उसके पति जावेद उर्फ चिकना को गिरफ्तार कर लिया गया। एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच शैलेन्द्र सिंह चौहान ने बताया कि जब्त चरस की कीमत करीब 7 लाख रुपए आंकी गई है।

पेडलर और सप्लाई चेन की जांच जारी

पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी चरस कहां से लाते थे और उनके नेटवर्क में कौन-कौन शामिल है। तीनों आरोपियों से पूछताछ जारी है।

जल गंगा संवर्धन अभियान के सहभागी सभी विभाग डैशबोर्ड में अनिवार्य रूप से दर्ज करें जानकारी : अपर मुख्य सचिव

कार्यों के प्रगति की समीक्षा कर दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

भोपाल (नप्र)। जल गंगा संवर्धन अभियान 2026-अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्रीमती दीपाली रस्तोगी ने जल गंगा संवर्धन अभियान के सहभागी विभागों के नोडल अधिकारियों के साथ बैठक की। विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की। सभी विभागों के नोडल अधिकारियों को रैंकिंग के लिए बनाए गए डैशबोर्ड में अनिवार्य रूप से समय पर जानकारी दर्ज करने के निर्देश दिए। जिससे अभियान की प्रगति का प्रभावी मूल्यांकन सुनिश्चित किया जा सके। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में वर्षा जल की प्रत्येक बूंद को सहेजने तथा पारंपरिक जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से प्रदेश में 19 मार्च से जल गंगा संवर्धन अभियान संचालित किया जा रहा है। अभियान से जुड़े 18 विभागों द्वारा जल संरक्षण एवं पर्यावरण संवर्धन को लेकर विभिन्न प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं, इससे प्रदेश में जल संसाधनों के संरक्षण को नई दिशा मिल रही है। अपर मुख्य सचिव श्रीमती रस्तोगी ने 19 मार्च से अब तक किए गए कार्यों की विभाग वार प्रगति की समीक्षा कर सभी विभागों को अभियान का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन सुनिश्चित करने और निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। आयुक्त, म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद श्री अवि प्रसाद ने बैठक में सहभागी विभागों के नोडल अधिकारियों से विभागवार प्रगति की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि सभी विभाग मॉनिटरिंग एवं रिपोर्टिंग के लिए बनाए गए डैश बोर्ड में अनिवार्य रूप से जानकारी दर्ज करें। डैश बोर्ड के माध्यम से अभियान की प्रगति की विभागवार रैंकिंग भी की जाएगी। बैठक में सहभागी विभागों द्वारा अभियान अंतर्गत संचालित की जा रही गतिविधियों के बारे में जानकारी दी गई। बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास, नगरीय प्रशासन एवं आवास, जल संसाधन, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, उद्यानिकी, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, पर्यावरण, महिला एवं बाल विकास, स्कूल शिक्षा, राजस्व, संस्कृति और जन अभियान परिषद सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की विस्तृत समीक्षा की

स्वास्थ्य संस्थाओं में लंबित आउटसोर्स पदों पर भर्ती की कार्यवाही प्राथमिकता के साथ शीघ्र पूर्ण किया जाए: शुक्ल

भोपाल। उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने मंत्रालय में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की विस्तृत समीक्षा की। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने निर्देश दिए कि प्रदेश के समस्त जिलों में स्वास्थ्य संस्थाओं में लंबित आउटसोर्स पदों पर भर्ती की कार्यवाही प्राथमिकता के साथ शीघ्र पूर्ण की जाए। उन्होंने आयुष्मान योजना अंतर्गत संबद्ध अस्पतालों में एनएबीएच मान्यता की अनिवार्यता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, जिससे मरीजों को गुणवत्तापूर्ण उपचार उपलब्ध हो सके। बैठक में 6 माह के सोनोग्राफी कोर्स पूर्ण करने वाले उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को शीघ्र प्रमाण पत्र प्रदान किए जाने की प्रक्रिया को समयबद्ध रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। साथ ही मेडिकल कॉलेज ग्वालियर में सीटीवीएस एवं ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग की स्वीकृति के लिए आवश्यक कार्यवाही में तेजी लाने पर बल दिया गया।

उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि प्रदेश सरकार आमजन को बेहतर, सुलभ एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी योजनाओं एवं कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें तथा निर्धारित समय-सीमा में परिणाम दें। उन्होंने यह भी कहा कि सुपरस्पेशलिटी सेवाओं में निरंतर भर्ती प्रक्रिया जारी रखी जाए, ताकि प्रदेश के नागरिकों को उच्चस्तरीय चिकित्सा सुविधाएं अपने ही राज्य में उपलब्ध हो सकें। बैठक में विभागीय कार्यों की प्रगति की विस्तार से समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए।

उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने बुधनी, दमोह एवं छतरपुर मेडिकल कॉलेजों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत नर्सिंग कॉलेजों में नर्सिंग शिक्षकों के 59 राजपत्रित पदों पर भर्ती हेतु मांग पत्र लोक सेवा आयोग को तत्काल प्रेषित करने के निर्देश दिए। बैठक में सीसीएचबी में नवीन पदों के सृजन के लिए प्रस्ताव तैयार करने और जिला चिकित्सालय राजगढ़ में रैन बसेरे के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि कि इन सभी कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए और प्रगति की समीक्षा समय-समय पर की जाए। प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा श्री अशोक बर्नवाल, आयुक्त श्री धनराजू एस सहित विभागीय वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

उप मुख्यमंत्री शुक्ल से मध्य प्रदेश चावल उद्योग महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने की सौजन्य भेंट

भोपाल। उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल से मध्य प्रदेश चावल उद्योग महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने मंत्रालय में सौजन्य भेंट की। इस दौरान प्रदेश के राइस मिलर्स की विभिन्न समस्याओं एवं उद्योग से जुड़ी चुनौतियों पर संक्षिप्त चर्चा हुई। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि प्राप्त सुझावों एवं समस्याओं का परीक्षण कर उनके यथोचित निराकरण हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। मध्य प्रदेश चावल उद्योग महासंघ के कार्यकारी अध्यक्ष श्री दिलीप सिंह सहित संघ के अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

डिस्पोजल फैक्ट्री में लगी आग, दो झुलसे

50 लाख से ज्यादा का नुकसान, समय रहते घर से निकाले 28 लाख रुपए

छिंदवाड़ा (नप्र)। छिंदवाड़ा के सोनपुर रोड स्थित एक डिस्पोजल फैक्ट्री में रविवार और सोमवार की दरमियानी रात करीब 2 बजे अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरी फैक्ट्री जलकर खाक हो गई। देर रात लगी आग पर सुबह 6 बजे के बाद काबू पाया गया लेकिन बीच-बीच में धुआं अभी भी उठ रहा है।

आग बुझाने के लिए दमकल की 5 गाड़ियां लगातार पानी डालती रही। इसके अलावा नगर निगम के 4 टैंकर भी मौके पर लगाए गए थे, लेकिन फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में रखे पॉलीथिन और डिस्पोजल सामग्री के कारण आग तेजी से फैलती गई।

फैक्ट्री मालिक और परिवार भी झुलसे

यह फैक्ट्री दीपक साहू (30) पिता लालचंद साहू की बताई जा रही है। आग लगने के समय फैक्ट्री परिसर में बने घर में उनका परिवार मौजूद था। आग की चपेट में आने से एक बुजुर्ग झुलस गए। उन्हें बचाने के प्रयास में फैक्ट्री संचालक दीपक साहू भी घायल हो गए। बुजुर्ग को तुरंत अस्पताल भेजा गया, वहीं डॉक्टर मनन गोगिया ने मौके पर पहुंचकर दीपक साहू का प्राथमिक उपचार किया।

लू भी चलेगी भोपाल, इंदौर-उज्जैन संभाग के शहरों में पारा बढ़ा

आंधी-बारिश खत्म, 16 से भीषण गर्मी

भोपाल (नप्र)। आंधी-बारिश का दौर खत्म होते ही मध्य प्रदेश में तेज गर्मी का असर शुरू हो गया है। रविवार को 5 शहरों में दिन का तापमान 40 डिग्री के पार रहा। रतलाम में सबसे ज्यादा 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

मौसम केंद्र भोपाल की माने तो प्रदेश में अब भीषण गर्मी पड़ेगी। 16 अप्रैल से हीट वेव यानी, लू का असर शुरू होगा। मौसम विभाग के अनुसार, मालवा-निमाड़ यानी, इंदौर और उज्जैन संभाग के शहर सबसे गर्म हैं। रविवार को इन्हीं शहरों में पारा बढ़ा हुआ रहा।

रतलाम के बाद खजुराहो में 40.4 डिग्री, धार, मंडला-नर्मदापुरम में 40.2 डिग्री, दमोह, रीवा-टीकमगढ़ में 39.5 डिग्री, खरगोन में 39.2 डिग्री, रायसेन, छिंदवाड़ा, उमरिया, सतना और मलाजखंड में पारा 39 डिग्री, बैतूल-सागर में 38.8 डिग्री, गुना-शाजापुर में 38.4 डिग्री, नौगांव में 38.2 डिग्री,

खंडवा में 38.1 डिग्री, सिवनी-सीधी में 38 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। प्रदेश के 5 बड़े शहरों की बात करें तो इंदौर में सबसे ज्यादा 39.2 डिग्री, भोपाल में 38.6 डिग्री, ग्वालियर में 36.1 डिग्री, उज्जैन में 38.5 डिग्री और जबलपुर में पारा 38.7 डिग्री सेल्सियस रहा।

15 अप्रैल से नया सिस्टम, पर असर नहीं, लू चलेगी- मौसम विभाग के अनुसार, 15 अप्रैल को नया सिस्टम एक्टिव हो रहा है, लेकिन यह कमजोर रहेगा। यानी, अब प्रदेश में तेज गर्मी वाला दौर ही रहेगा। गर्मी बढ़ने से लोग उससे बचने के तरीके भी तलाश रहे हैं।

कोई मुंह पर कपड़ा बांधकर घर से बाहर निकल रहा है तो कोई गन्ने का ज्यूस, कोल्ड्रिंक्स, आइस्क्रीम का लुत्फ उठा रहा है। गर्मी का असर बढ़ते ही मौसम विभाग ने बचाव की एडवाइजरी भी जारी की है।

लोगों से कहा गया है कि वे दिनभर पर्याप्त पानी पिएं और शरीर को हाइड्रेट रखें। दोपहर के समय लंबे समय तक धूप में न रहे। हल्के वजन और रंग के सूती कपड़े पहनें। बच्चे और बुजुर्ग खासतौर पर ध्यान रखें। वहीं, 16 अप्रैल से तेज गर्मी का दौर शुरू हो जाएगा। धार, खरगोन, खंडवा, सीधी और सिंगरौली में लू चलने का अलर्ट है।

तमिलनाडु में डिजिटल अरेस्ट कर ठगे 67 लाख

रतलाम में एक अकाउंट में जमा हुआ 47 लाख, खाताधारक समेत तीन लोग गिरफ्तार

रतलाम (नप्र)। तमिलनाडु के कोयंबटूर के एक शख्स को डिजिटल अरेस्ट कर 67 लाख 75301 रुपए ठगे गए। ठगी गई राशि का एक हिस्सा 47 लाख 75,301 रुपए रतलाम में फेडरल बैंक के एक अकाउंट में जमा हुआ। रतलाम पुलिस ने रविवार को संबंधित जिस खाते में रुपए जमा हुए उसके खाता धारक और दो अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है। रतलाम के खाता धारक का बैंक अकाउंट म्यूल अकाउंट के रूप में यूज किया है। इसके बदले खाताधारक को कमीशन देने की बात सामने आई है। एसपी अमित कुमार ने बताया नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर केसी श्रीधर निवासी कोयंबटूर (तमिलनाडु) द्वारा Online Financial Fraud (Internet Banking Fraud) की शिकायत दर्ज की गई। शिकायतकर्ता को फ्राडस्टर्स द्वारा 'डिजिटल अरेस्ट स्कैम' कर कुल धोखाधड़ी 67,75,301 रुपए ठगे गए। कोयंबटूर पुलिस द्वारा जांच में पाया कि उक्त धोखाधड़ी की राशि का एक हिस्सा रतलाम में संबंधित फेडरल बैंक खाते में जमा हुआ है। इससे स्पष्ट हुआ कि यह खाता मल्टी-स्टेट साइबर फ्रॉड नेटवर्क में यूज किया गया।

रतलाम के तीन लोग गिरफ्तार- जांच के दौरान समन्वय पोर्टल से प्राप्त जानकारी के अनुसार फेडरल बैंक का खाता संदिग्ध पाया गया। नोडल अधिकारी फेडरल बैंक से जानकारी प्राप्त करने पर पता चला कि उक्त खाता खाताधारक प्रथम मित्तल (23) निवासी माणकचौक, रतलाम के नाम पर है। उक्त खाते के ट्रांजेक्शन के बारे में जांच की गई। पता चला कि 25 मार्च 2026 को प्रथम मित्तल के खाते में 47,75,301 रुपए की संदिग्ध राशि जमा हुई थी।

लालच में खुलवाया म्युल अकाउंट

नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर दर्ज शिकायत के अनुसार आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 318(4) के अंतर्गत केस दर्ज कर मामला जांच में लिया। रतलाम पुलिस के पास मामला पहुंचने पर बैंक खाते की जांच कराई। खाता धारक प्रथम मित्तल को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की। खाताधारक प्रथम ने बताया कि उसने अपने दो साथियों हेमंत रायक उर्फ मोनू निवासी रुद्राक्ष कॉलोनी व शुभम रेडा निवासी निवासी नागरवास रतलाम के कहने पर कमीशन के लालच में म्युल अकाउंट खुलवाना स्वीकार किया। माणकचौक थाना पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ धारा 318(4) के अंतर्गत केस दर्ज कर गिरफ्तार किया। एसपी के अनुसार अन्य संलिप्त आरोपियों एवं नेटवर्क की कड़ियों की तलाश की जा रही है। अंतरराज्यीय साइबर फॉड से मिली लिंक के आधार पर हर एक पहलुओं को जांच कर रहे है।

सौजन्य भेंट

राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल से लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्यमंत्री श्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल ने आज लोकभवन में सौजन्य भेंट की।

संपादकीय

पश्चिम एशिया: हालात और बिगड़े

इस्लामाबाद में ईरान अमेरिका वार्ता असफल रहने के बाद पश्चिम एशिया के हालात और गंभीर हो गए हैं। जहां अब अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी कर दी है, वहीं कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आ गया है। इसका वैश्विक व्यापार पर विपरीत असर पड़ने लगा है। पाकिस्तान को मध्यस्थ बनाकर अमेरिका ने ईरान से सीधी बातचीत की जो पहल की थी, उसके सफल होने की संभावना यूं तो वैसे भी कम ही थी, क्योंकि इस वार्ता में युद्ध का तीसरा पक्ष इजराइल शामिल नहीं था। ऐसे में दोनो देशों के बीच 21 घंटे तक चली बातचीत के बाद भी मुख्यब मुद्दों पर सहमति न बन पाने के कारण वार्ता बेनतीजा रही। हालांकि दोनों पक्ष इसके लिए एक-दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कहने को दोनों देशों के बीच युद्ध विराम लागू है, लेकिन कब फिर से जंग भड़क जाए, कहा नहीं जा सकता। क्योंकि ताजा हालात में ईरान के बाद अब अमेरिका के होर्मुज स्ट्रेट की नाकाबंदी कर दी है। कहा यही जा रहा है कि अमेरिका को शक है कि कुछ देशों के जहाज चीनी मुद्रा युआन में टोल देकर होर्मुज स्ट्रेट से निकले हैं। अमेरिका ऐसे देशों को सख्ती से रोकेगा और बगैर उसकी इजाजत किसी देश का जहाज वहां से नहीं गुजर पाएगा। अमेरिका का कहना है कि जो कोई भी जहाज होर्मुज़ स्ट्रेट में गैरक़ानूनी टोल देगा, उसे खुले समुद्र में सुरक्षित रास्ता नहीं मिलेगा। साथ ही अमेरिका अपने सहयोगी देशों के जहाज़ों के सुरक्षित आवागमन को सुनिश्चित करने के लिए होर्मुज़ स्ट्रेट से बारूदी सुरंगों को हटाना जारी रखेगा। कहा यह भी जा रहा है कि 'अमेरिकी सेना सही समय पर ईरान के खिलाफ़ हमले फिर से शुरू करने के लिए तैयार है। इससे दुनिया भर में ऊर्जा संकट और गहराने लगा है। यह तय करना कठिन है कि किस देश के जहाज ने टोल दिया और किसने नहीं दिया। समूचा घटनाक्रम जिस दिशा में जा रहा है, उससे हालात सुधरने की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। रविवार को अमेरिकी क्रूड ऑयल की कीमत आठ प्रतिशत बढ़कर 104.24 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई। वहीं, अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत सात प्रतिशत बढ़कर 102.29 डॉलर प्रति बैरल हो गई। यही दरें युद्ध शुरू होने के समय 70 डॉलर प्रति बैरल थीं। अब लड़ाई होर्मुज स्ट्रेट पर नियंत्रण के लिए शुरू हो गई है। अमेरिका इसे खुलवाना चाहता है तो ईरान इस पर अपना नियंत्रण कायम रखना चाहता है, जबकि होर्मुज अंतरराष्ट्रीय जल सीमा में आता है, कानूनन ईरान इस पर अपना नियंत्रण नहीं कर सकता है, लेकिन अब सभी जगह अंतरराष्ट्रीय कानूनों की खुलेआम धज्जियां उड़ रहीं हैं और कोई इसे रोक नहीं पा रहा है। जबकि दुनिया के व्यापारिक तेल का लगभग पांचवां हिस्सा हर दिन होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर गुजरता है। सऊदी अरब, इराक, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और ईरान जैसे प्रमुख तेल निर्यातक देश इसी मार्ग पर निर्भर हैं। खाड़ी के देशों का तो दाना पानी ही इस जल मार्ग पर निर्भर है। वो न तो चीजें आयात कर पा रहे हैं और न ही निर्यात कर पा रहे हैं। भारत जैसे देशों के लिए तो और भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। क्योंकि एक तरफ तेल और गैस की सुगम आपूर्ति की उम्मीदें नहीं है, वहीं भारत से खाड़ी देशों को होने वाला निर्यात भी ठप हो गया है। परिणास्वरूप देश में सैंकड़ों फैक्टरियां बंद हो गई हैं और करीब 1 लाख से ज्यादा मजदूर सड़क पर आ गए हैं। अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों ने भारत की आर्थिकी की वृद्धि दर को घटाना शुरू कर दिया है। कुल मिलाकर हालात चिंताजनक हैं।

आज अगर बाबा साहब होते

नजरिया

रघु ठाकुर

लेखक समाजवादी विचारक हैं।

14 अप्रैल डॉ. बाबासाहब अम्बेडकर का जन्म दिन है। इस अवसर पर वे किस सन् में पैदा हुए या किस सन् में उनकी मृत्यु हुई यही बात महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि आज अगर बाबासाहब जिंदा होते तो अपनी मान्यताओं, विचारों व स्थापनाओं की रक्षा के लिये, उन्हें किन-किन शक्तियों से जुझना पड़ता। मैं समझता हूँ कि बाबासाहब को सर्वाधिक निराशा या अंतरू संघर्ष उन लोगों से ही करना पड़ता जिनकी तरक्की व समता के लिये उन्होंने आजीवन संघर्ष किया। वे अपने जीवन के अंतिम दिनों में कहते भी थे कि मुझे सबसे ज्यादा शिकायत उन अपने ही लोगों से है, जिन्होंने मेरी बातों को या तो नजरअंदाज किया या फिर मुझे केवल पूजने की प्रतिमा बना दिया।

अक्सर देश या दुनिया में ऐसी धारणा बनी है कि बाबा साहब केवल दलितों के नेता थे या उन्होंने केवल दलित उत्थान के लिये कार्य किया, परन्तु यह आंशिक सत्य हैं। निःसंदेह बाबा साहब दलितों के उत्थान व उन्हें बराबरी दिलाने के लिये एक सतत संघर्षशील सेना नायक थे परन्तु उन्होंने समूचे समाज को बराबरी, प्रगतिशील व मानवीय समाज बनाने के लिये अपना जीवन लगा दिया। उन्हें केवल दलितों का नेता या मसीहा कहा जाना उन्हें जाति के अंदर सिकोड़ना होगा।

बाबा साहब जिन्हें आमतौर पर संविधान निर्माता या संविधान शिल्पी कहा जाता है, अपने द्वारा प्रस्तुत किये गये संविधान की सीमाओं को वह बेहतर जानते थे । इसीलिये उन्होंने संविधान पारित होने के तत्काल बाद विधि मंत्री के नाते अपने प्रथम साक्षात्कार में कहा था कि श्आज हम अंतर्विरोध के एक नये युग में प्रवेश कर रहे हैं जिसमें राजनैतिक समानता तो होगी यानी एक व्यक्ति - एक वोट परन्तु आर्थिक व सामाजिक समानता नहीं होगी। बाबा साहब ने संविधान की जिन सीमाओं को उसके पारित होने के कुछ ही दिनों बाद पहचाना था, आज देश उन संवैधानिक समस्याओं से रुबरु हो रहा है। पिछले कुछ वर्षों से देश की सर्वोच्च न्यायपालिका व विधायिका तथा सत्ता के टकराव के जो मामले सामने आ रहे है, वे इसी का घोतक है। संविधान का मूल खंड भी अपने लक्ष्यों में लगभग असफल जैसा किया जा रहा, ऐसा प्रतीत हो रहा है।

बाबा साहब यह जानते थे कि परिवर्तनशीलता का गुण विकास के लिये जरुरी है। उन्होंने इमर्सन को उद्धृत करते हुये कहा था कि स्थिरता गधे का गुण उन्होंने अपने विचारों में भी, समय-समय पर बड़े परिवर्तन किये जो उनके अनुभवों पर आधारित थे।

बाबा साहब में भारतीयता गहरे तक थी। उनके दो ही लक्ष्य थे एक भारत महान बने और दूसरा श्सामाजिक अन्याय समाप्त हो।य जो लोग उन पर यह आरोप करते है कि वे भारत की आजादी के पक्ष में नही थे, वे उनका गलत विश्लेषण करते है।

वे भारत को आजाद देखना चाहते थे परन्तु उसके पूर्व या साथ में अपनी दलित कौम की भी आजादी चाहते थे। उनके मन में यह संशय अवश्य रहता था जो कि स्वाभाविक भी था कि कहीं ऐसा न हो कि देश तो आजाद हो जाये परन्तु देश की अनुसूचित जातियाँ,उच्च जातियों की गुलाम बनी रह जायें। इसीलिये उन्होंने 1938 में बंबई विधानसभा में कहा था कि श्मुझे अकसर गलत समझा जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिये कि मैं अपने देश से प्यार करता हूँ लेकिन मैं इस देश के लोगों को यह बात भी साफ-साफ बता देना चाहता हूँ कि मेरी एक और निष्ठा है जिसके लिये मै प्रतिबद्ध हूँ। यह निष्ठा है अस्पृश्य समुदाय के प्रति जिसमें मैने जन्म लिया है और मैं इस सदन में पूरे जोर-शोर से कहना चाहता हूँ कि जब कभी देश हित और अस्पृश्यों के हित के बीच टकराव होगा तो मैं अस्पृश्यों के हितों को तरजीह दूँगा। पर अगर मेरे अपने हित और देश हित के साथ टकराव होगा तो मैं देश हित को तरजीह दूँगा।य बाबा साहब के मन में भारतीय राष्ट्रवाद बहुत स्पष्ट था। वे भाषावार प्रांतों के विरोध में थे क्योंकि वे महसूस करते थे कि भाषावार प्रांत आगे जाकर किसी दिन क्षेत्रवाद व देश के विभाजन के कारण बन सकते हैं। उनके ही शब्दों में भाषावार प्रांतों में छोटे-छोटे समुदायों अर्थात् अल्पसंख्यक जातियों का क्या भविष्य है? क्या ये विधायिका में चुने जाने की आशा रखें? क्या उन्हें राज्य सेवा में कोई पद मिलने की आशा है? उनकी आर्थिक उन्नति के लिये क्या कोई ध्यान देने वाला हैं? इन परिस्थितियों में भाषायी प्रांत के गठन का अर्थ होगा स्वराज को किसी एक बहुसंख्यक समुदाय के हाथों सौप देना। जो लोग समस्या के इस पहलू को नहीं समझते या समझना नहीं चाहते वे इसे तभी भली-भांति समझेंगे जब हम भाषायी राज्य जैसे शब्द का प्रयोग न कर जाट राज्य, रेड्डी राज्य या मराठा राज्य कहेंगे। जो ऐसे समेकन या एकीकरण की मांग करते है उनसे पूछा जाना चाहिए कि क्या वे अन्य राज्यों के साथ युद्ध करने जा रहे है? यदि समेकन से पृथकता का भाव पुष्ट होता है तो आगे चलकर हमारा भारत ठीक उसी स्थिति में पहुँच जायेगा जैसी स्थिति इस देश की मौर्य साम्राज्य के पतन या बिखराव के बाद हुई थी। क्या भाग्य हमें उसी ओर धकेल रहा है।

भाषावार राज्यों के गठन के बारे में जो चेतावनी बाबा साहब ने 1938 में दी थी। वह आज स्पष्ट नजर आती है। भाषावाद राज्यों के गठन से भाषावाद की कट्टरता व क्षेत्रीयता बढ़ी है तथा राष्ट्रीय एकता कमजोर हुई है। शिवसेना पर भी असर हुआ है, कहते थे कि श्आमची मुंबई मराठी मुंबई या अन्य प्रांतों के निवासियों को हेय दृष्टि से श्भैया माणुस्य कहकर अपमानित करते है या फिर अन्य राज्यों के निवासियों के साथ दंगे फसाद कर उन्हें भगाने का प्रयास करते है तो बाबा साहब की 88 वर्ष पूर्व दी गई चेतावनी याद आ जाती है। आज ये राष्ट्रीय हितों के बजाय क्षेत्रीय हितों के पर्याय बन रहे है। आजादी के 78 वर्ष के बाद भी कर्नाटक व तमिलनाडू के बीच कावेरी जल विवाद नहीं सुलझ पाया। पंजाब तथा हरियाणा के बीच सतलज, यमुना, जल विवाद नहीं निपट पाया। क्षेत्रीय भाषा प्रेम या मातृभाषा, प्रेम, भाषावाद में संकुचित हो रहा है जिसके परिणाम स्वरुप राष्ट्रभाषा का फैलाव भी रुक गया है। आज तमिलनाडू ,पंजाब,बंगाल, केरल, तेलंगाना, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा में क्रमशः तमिल, गुरुमुखी, बंगाली, मलयाली, तेलगू, कन्नड़ या उड़िया के साथ अंग्रेजी होती है न कि हिन्दी या हिन्दुस्तानी हिन्दी के विरोध में क्षेत्रीय राजनैतिक शाक्तियाँ दंगे कराने को तत्पर रहती है परन्तु अंग्रेजी पर उन्हें कोई गुस्सा नहीं आता। अगर राज्य केवल एक ही भाषा व परंपराओं के लोगों का बंद किला बन जायेगा तो भारत राष्ट्र कहाँ व कब तक टिकेगा, क्या मजबूत बनोगे? यह जो प्रश्न बाबा साहब ने खड़ा किया था अब आज और ज्यादा प्रांसगिक हो गया है। उनके मन में अपना राष्ट्रप्रेम कितना गहरा था इसका प्रमाण उनके इस कथन से मिल जाता है श्मुझे अच्छा नहीं लगता जब कुछ लोग कहते है हम पहले भारतीय हैं बाद में हिन्दू या मुसलमान, मुझे यह स्वीकार नही है। धर्म, संस्कृति, भाषा आदि की प्रतिस्पर्धा निष्ठा के साथ रहते हुये भारतीयता के प्रति निष्ठा नहीं पनप सकती। मैं चाहता हूँ कि लोग पहले भी भारतीय हों और अंत तक भारतीय रहे, भारतीय के अलावा कुछ नहीं। आज कितने राष्ट्रवादी यह कह सकते हैं, चाहे वे किसी भी मजहब के क्यों न हों पहले भी भारतीय हैं तथा बाद में भी भारतीय हैं।

आज कुछ ऐसी जमाते देश में है जो बाबा साहब का नाम श्तोता रंटत्य लेती है या फिर बाबा साहब को अपने सामाजिक समूह का बड़ा व्यक्ति मानकर उनका नाम लेते है परन्तु बाबा साहब के विचारों को अपने कार्यो से खंडित करते है। ऐसे मित्र बाबा साहब के अनुयायी नहीं है बल्कि केवल मूर्ति पूजक है जबकि बाबा साहब कहते थे कि वे मूर्ति भंजक है। (नोट-मूर्ति तोड़क नही)

स्व. कांशीराम जी या मायावती जी जब भारतीय समाज व्यवस्था को, जो सीधी लाईन की व्यवस्था है जिसमें कोई नीचे है कोई ऊपर, उलटना चाहते हैं ताकि नीचे वाला ऊपर आ जाये, बीच वाला ज्यों का त्यों रहे तथा ऊपर वाला नीचे चला जाये तो वे जाति व्यवस्था को नष्ट नहीं करना चाहते बल्कि अपनी जाति को शोषक व श्रेष्ठ जाति के शीर्ष स्थान पर बिठाना चाहते हैं। बाबा साहब ने तो एक पुस्तक भी लिखी थी श्एनीहेलेशन आफ कास्ट्य (जाति प्रथा की समाप्ति)। वे जाति प्रथा को, जो जन्मना भेदभाव की व्यवस्था है, समाप्त करना चाहते थे। डॉ. राम मनोहर लोहिया कहते थे कि-'भारतीय खड़ी लाईन की समाज व्यवस्था को आड़ी यानि समान समाज व्यवस्था में बदलना होगा जिसमें न कोई छोटा होगा न कोई बड़ा बल्कि सभी समान होंगे, समान पैदा होगे,समान मरेंगे। भारतीय विषमता मूलक जातीय व्यवस्था की ही पीड़ा थी जिसने बाबा साहब को यह कहने को बाध्य किया था कि मैं हिन्दू पैदा हुआ था परन्तु हिन्दू मरुँगा नहीं।य यद्यपि बाबा साहब धार्मिक व्यक्ति थे। आज उनका नाम लेकर राजनैतिक रोटियाँ सेंकने वाले कुछ लोग नवब्राम्हणवाद स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। वे जातिप्रथा की विषमता को मिटाना नहीं चाहते बल्कि अपनी जाति को श्रेष्ठ बनाना या शीर्ष पर बिठाना चाहते हैं तथा विद्यमान जाति व्यवस्था के शीर्ष पर बैठी जातियों को शूद्र याने शूद्र को ब्राम्हण बनाना व ब्राम्हण को शूद्र बनाना चाहते हैं।

यह भी उतना ही ब्राम्हणवादी सोच है जिस प्रकार ब्राम्हण को ब्रम्हा के मुख से पैदा होना तथा शूद्र को पैर से पैदा होना बताना। यह पुराने ब्राम्हणवाद का नव ब्राम्हणवाद में रुपांतरण करना होगा। यह समता की व्यवस्था नहीं होगी जिसे बाबा साहब बनाना चाहते थे।

बाबा साहब ने दूसरा शत्रु पूंजीवाद को घोषित किया था। वे पूंजीवाद मिटाना चाहते थे, न कि दलित पूंजीवाद चाहते थे। पर कुछ लोग जो बाबा साहब का नाम लेते हैं पूंजीवाद या विषमता को नहीं मिटाना चाहते वरन अपनी जाति के पूँजीवाद बनाना चाहते हैं। आज विषमता इतनी भारी है कि ऑक्सफैम के अनुसार देश के 166 लोगों के पास इतनी संपत्ति है जितनी देश की 70 करोड़ आबादी के पास। आज देश में 200-300 (खरबपति) बड़ी जातियों के लोग है जो देश की 100 करोड़ की आबादी का शोषण कर पूंजी के मलिक बने है। कल यदि इनमें से 5-10 दलित के घर में जन्मे, पूंजीपति बन जाये तो क्या देश के 20 करोड़ दलितों का उत्थान हो जायेगा? औसतन 53 लाख लोगों की कीमत पर एक अरबपति बनता हैं। वह चाहे सवर्ण बने या शूद्र। अगर 53 लाख शूद्रों की लाश पर एक दलित पूंजीपति बने तो क्या इससे शूद्रों का कोई भला होगा? यह व्यवस्था बाबा साहब की अभीष्ट नहीं थी। वे आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक समानता चाहते थे। वे समाजवाद चाहते थे जो सभी के लिये हो। बाबा साहब मूल उद्योगों को सरकारी रखना चाहते थे तथा निजी पूंजी को समता के बंधनों में कैद करना चाहते थे। क्या बाबा साहब के इन संदेशों को देश समझेगा, मानेगा और अमल में लायेगा? मैं सोचता हूँ कि अगर आज बाबा साहब होते तो, 1940-50 के दशक में तो वे अपनों से निराश थे पर 21वीं सदी के आरम्भ में अपनों व परायों के सामने समता व समाजवाद के संघर्ष की महाभारत में अर्जुन बनकर लड़ रहे होते।

अंबेडकर के भारत में आधी आबादी का नया नैरेटिव

जयंती पर विशेष

प्रो. कन्हैया त्रिपाठी

लेखक एनएचआरसी (इण्डिया) में स्पेशल मॉनिटर व केंद्रीय विश्वविद्यालय पंजाब में चेयर प्रोफेसर हैं।

भारतीय श्रेष्ठता हमारे भारतीय मनीषियों से ही स्थापित हुई है। डॉ. अंबेडकर ऐसी विभूतियों में सम्मिलित हैं जिन्होंने राष्ट्र निर्माण व सामाजिक परिवर्तन के लिए अभूतपूर्व कार्य किया। इस जन्म-पर्व के कुछ दिन बाद संसद में एक बार नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर चर्चा होने जा रही है। यह अधिनियम स्त्रियों की भागीदारी व सशक्तीकरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 106वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2023 है जिसको आकार मिलने पर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत यानि एक-तिहाई सीटें आरक्षित करता है। इस ऐतिहासिक कानून को 2029 तक लागू होने की बात की गयी है। यह अधिनियम मानें तो डॉ. भीमराव अंबेडकर के स्त्री-सशक्तीकरण के लिए की गयी संस्तुतियों की अगली कड़ी है। वह यह चाहते थे कि हमारी स्त्रियाँ सशक्त हों, सक्षम हों, समृद्ध हों और गरिमा के साथ हों। स्मरण आ रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नारी शक्ति वंदन सम्मेलन का संबोधन जहाँ उन्होंने साफ़-साफ कहा था कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम को समय पर लागू किया जाना चाहिए ताकि महिलाओं की भागीदारी से हमारा लोकतंत्र सुदृढ़ हो। डॉ. अंबेडकर के भारत में यह उनके ही विजन-प्लान का नया नैरेटिव है। वह स्त्रियों के खुशियों के लिए संपत्ति में भी भागीदारी के पैरोकार थे।

अब जब देश एआई और नई सूचना क्रांति के साथ आगे बढ़ रहा है तो निश्चय ही संभावनाओं और चुनौतियों के अपने-अपने तरीके से प्रभावित किया है। हमें संभावनाएं तो अवसर देती हैं लेकिन चुनौतियाँ बहुत पीछे धकेल देने को आतुर हैं। भारत सरकार के नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर दिए गए अभिभाषण को पढ़ें तो कई चीजें ऐसी निकलकर सामने आती हैं जिससे यह पता चलता है कि सरकार केवल हमें सपने नहीं दिखा रही है बल्कि स्त्रियों को सुरक्षा की गारंटी देने के लिए भी पूरी तरह तैयार है। यथा, हमारे समाज में एक बड़ी चुनौती महिला सुरक्षा को लेकर है तो इस दिशा में बहुत मजबूती से सरकार ध्यान दे रही है। न्याय व्यवस्था अधिक संवेदनशील, निर्णय प्रक्रिया तेज बनाने की पहल सरकार ने की है। इसके लिए कानूनी बदलाव की ज़रूरत है तो उसे भी सरकार कर रही है। फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों की स्थापना हो रही है। भारतीय न्याय संहिता में महिला सुरक्षा को प्राथमिकता ही नहीं दी जा रही है अपितु त्वरित निर्णय से महिलाओं को स्ट्रेस से फ्री करने और नई शुरुआत के लिए उन्हें अवसर देने की कोशिश शुरू हो चुकी है। पहले एफआईआर दर्ज करने में कितनी समस्याएं होती थीं। थाने भी एफ़ाईआर दर्ज नहीं करते थे अब प्रक्रिया को सरल बनाया दिया गया है। अब किसी भी स्थान से ई-एफआईआर या जीरो-एफआईआर दर्ज हो सकती है। पीड़िता के बयान को ऑडियो-वीडियो के माध्यम से रिकॉर्ड करने जैसी व्यवस्थाएं कर दी गयी हैं।

इतिहास की ओर मुड़कर देखें तो पता चलता है कि डॉ. भीमराव अंबेडकर की हिन्दू कोड बिल को लेकर पीड़ा का मुख्य कारण महिलाओं को समानता, संपत्ति और तलाक का अधिकार दिलाने के उनके प्रयासों का रूढ़िवादी ताकतों द्वारा कड़ा विरोध था। उन्होंने इसे भारतीय समाज में लैंगिक समानता की सबसे बड़ी क्रांति माना था लेकिन संसद में बिल को कमजोर करने और नेहरू द्वारा पीछे हटने के कारण, उन्होंने 1951 में कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। आज भारत में स्त्री शक्ति वंदन अधिनियम पर परिचर्चा और उन्हें 33 प्रतिशत तक के आरक्षण सुनिश्चित करने की बात हो रही है। यह है भारत का व्यापक बदलाव और इससे निश्चय ही भारत अब पूरी दुनिया को एक नया सन्देश देने जा रहा है।

आधी आबादी का सम्मान और राजनीति में उनकी भागीदारी बढ़ाना डॉ. अंबेडकर का सपना था। वह आधी आबादी को सदैव अपने साथ विकसित होते देखना चाहते थे। उन्होंने जब महाड़ सत्याग्रह किया तो उसमें स्त्रियाँ साथ थीं। आधी आबादी के साथ खड़े होकर आन्दोलनरत डॉ. अंबेडकर का विश्वास था की एक दिन हमारी स्त्रियाँ देश में अपना अहम् योगदान देंगी, भारत की तस्वीर बदलेंगी। डॉ. अंबेडकर के बारे में ऐसी मान्यता है कि बाबासाहेब ने औपनिवेशिक, पुरुष-प्रधान और विक्टोरियन नैतिकता पर आधारित जाति व्यवस्था को चुनौती दी थी। निष्क्रिय महिला की धारणा को तोड़ते हुए महिलाओं को अपनी आवाज़ उठाने का आधार दिया। हिन्दू कोड बिल हो या श्रम के बदले समान वेतन की बात, डॉ. अंबेडकर ने खुद इसके लिए आवाज़ बुलंद किया और वह चाहते थे कि स्त्रियाँ अपनी आवाज़ खुद बनें।

अंबेडकर की लैंगिक-समानता पर आज दुनिया भर में विचार हो रहे हैं। खासकर एसडीजी-2030 में इक्विटी व इक्वैलिटी के जहाँ कहीं भी डिस्कोर्स छिड़ रहे हैं तो डॉ. अंबेडकर वहां स्मरण किए जा रहे हैं। महिला मंडल बंबई, बहिस्कृत महिला सेवा मंडल, धोबी तलाव सोमवंशीय महिला मंडल, चर्मकार महिला मंडल, चन्दनवाणी महिला मंडल, दादर महिला मंडल, कमरीपूरा की महार महिलाएं और ऐसे अनेक संघटकों की महिलाओं के साथ तो डॉ. अंबेडकर जुड़े हुए थे लेकिन देश की अनेक महला संगठनों के साथ वह जुड़कर स्त्रियों के सशक्तीकरण के लिए खुद खड़े मिलते हैं, इतिहास में यह सारी बातें दर्ज हैं की डॉ. अंबेडकर का स्त्रियों के लिए क्या जुडाव था और वह स्त्रियों के हित के लिए क्या सोचते थे। 17 जून 1936 डॉ. अंबेडकर का संवाद टाइम्स ऑफ़ इण्डिया ने प्रकाशित किया था। उसमें डॉ. अंबेडकर ने साफ़-साफ कहा था कि जब तक आप अपनी जीवनशैली बदलने के लिए तैयार नहीं होते, हमें आपसे कुछ लेना-देना नहीं है, और हम आपके किसी काम के नहीं हैं। आपके लिए केवल दो रास्ते हैं या तो आप वहीं रहें जहां आप हैं और तिरस्कृत होती रहें तथा सबसे बची रहें, या फिर आप अपना शर्मनाक व्यवसाय छोड़ दें और हमारे साथ आ जाएं। आप मुझसे पूछेंगी कि आप अपनी जीविकोपार्जन कैसे करेंगी। मैं आपको इस संबंध में कुछ बताने नहीं जा रहा हूँ। इसके सैकड़ों तरीके हैं। लेकिन मैं आग्रह करता हूं कि आप यह निम्नकोटि का जीवन छोड़ दें। आपको अन्य वर्गों की महिलाओं के समान ही विवाह करके सामान्य घरेलू जीवन व्यतीत करना चाहिए और उन स्थितियां नहीं रहना चाहिए जो अपरिहार्य रूप से आपको वेश्यावृति में खींच ले जाती हैं। इस लेवल पर डॉ. अंबेडकर सोचते थे। वह स्त्रियों को अपने अस्तित्व व गरिमा की यद् दिलाते थे और कहते थे कि अपने अभिशप्त जीवन को छोड़ो, आगे बढ़ो और अपने आने वाली पीढ़ी को सन्देश दो कि हम किसी भी दलदल में फंसकर जीने से ज्यादा अच्छा है संघर्ष करके आगे बढ़ें।

डॉ. अंबेडकर ने कहा था मैं किसी समुदाय की प्रगति का मूल्यांकन महिलाओं द्वारा की गई प्रगति से करता हूं, और जब मैं ऐसी सभा को देखता हूं तो मुझे विश्वास और प्रसन्नता दोनों ही होती हैं कि हमने प्रगति की है। मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा जोकि मैं समझता हूं कि आपको अपने मस्तिष्क में रखनी चाहिए। साथ रहना सीखें, सभी बुराइयों से दूर रहें। अपने बच्चों को शिक्षा दें। उनमें महत्वाकांक्षा पैदा करें। उनके मस्तिष्क में यह बात भरें कि उन्हें महान बनना है। उनके मन से सभी प्रकार की हीन भावनाओं को निकाल दें। विवाह करने की जल्दी न करें, विवाह एक जिम्मेदारी है। आपको इसे अपने बच्चों पर नहीं थोपना चाहिए जब तक कि वे विवाह से उत्पन्न होने वाले दायित्वों को पूरा करने में वित्तीय रूप से सक्षम न हो जाएं। डॉ. अंबेडकर के यह विचार अखिल भारतीय दलित वर्ग महिला सम्मेलन के दूसरे सत्र में नागपुर में 20 जुलाई, 1942 को अभिव्यक्त हुए हैं। सोचिये कि वर्षों पहले डॉ. अंबेडकर की स्त्रियों के बारे में क्या सोच थी। आज जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर संसद में एक बार हम राष्ट्रव्यापी बहस के साथ डॉ. अंबेडकर को स्मरण करें तो यह लगता है कि डॉ. अंबेडकर के आधी आबादी के नैरेटिव को वर्तमान सरकार नया आकार ही देकर स्त्रियों के सशक्तीकरण की दिशा में आगे बढ़ रही है जो भारत के विकसित स्वरूप का नया अध्याय होगा। आज बाबासाहेब डॉ. अंबेडकर के जन्म पर्व पर उन्हें स्मरण आकर अगर हम स्त्रियों के सम्मान के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो निश्चय ही यह डॉ. अंबेडकर के भारत को बनाने की एक सच्ची कोशिश है। इसे अच्छा डॉ. अंबेडकर का स्मरण हो ही नहीं सकता।

अंबेडकर : एक व्यक्ति नहीं विचार

जयंती पर विशेष

विजय जोशी

लेखक भेल भोपाल के पूर्व ग्रुप महाप्रबंधक हैं।

हमारे स्वाधीनता इतिहास के संदर्भ में कहा गया है जिन लोगों की कुर्बानी पर चलकर आज़ादी आई, उनकी याद बहुत ही गहरी लोगों ने दफनाई. आज़ादी पश्चात के दौर में तो अलग अलग विचारधारा के पोषक लोगों ने अपनी सुविधानुसार हमारे इतिहास को बंधक लिया. फिर भले ही वे दक्षिणपंथी हों, वामपंथी हों या फिर सहुलियत अनुसार गुलाटी मारने वाले मध्य मार्गी. सबके अपने सत्ता केंद्र हैं. नई पीढ़ी भ्रमित है. इतना विनाश तो अंग्रेज भी नहीं कर पाये थे जो हमारे अपनों ने किया.

बाबा साहेब अंबेडकर एक व्यक्ति नहीं विचार थे. दलितों का मसीहा कहना उन्हें सीमाओं में बांधने का प्रयास है और उनके साथ अन्याय. मसीहा किसी एक कौम का कैसे हो सकता है. उसका जन्म तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के उद्देश्य से होता है. बाबा साहब की पारिवारिक पृष्ठभूमि मराठी थी. उनके पूर्वज महाराष्ट्र के रत्नागिरी के मूल निवासी थे, जिनके कुल का नाम सपकाल था. अंबेडकर उनके शिक्षक थे, जिनका नाम उन्होंने आदर सहित अपनाया. मराठी भाषा में ऐसे नाम ब्राम्हण समुदाय से संबंध रखते हैं, जिसकी लाज उनके द्वारा सदैव रखी गई.

उनके साथ न्याय न तो देश के स्वघोषित बुद्धिवादी वर्ग ने किया और न ही उनके अनुयायियों ने. वे बहुत बड़े कानूनविद, समाज सुधारक तथा सुलझे हुए विचारक थे. ऐसा नहीं होता तो इतनी विसंगतियों से उलझे देश को एक विस्तृत हर पहलू को छू लेने वाला संविधान कैसे दे पाते. उनके इन पहलूओं को नज़रअंदाज़ ही कर दिया गया है. दरअसल वे आर्थिक यथार्थ के बहुत बड़े विश्लेषक थे. वे कहा करते थे कि अगर उन्होंने राजनीति को न चुना होता तो अर्थशास्त्र के शिक्षक होना पसंद करते.

यदि तत्कालीन राजनैतिक नेतृत्व ने कुर्सी की लालसा को परे रखते हुए थोड़ा भी सब्र एवं सहनशीलता दिखाई होती तो देश का विभाजन टाला जा सकता था. अंग्रेजों से आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे मोहम्मद अली जिन्ना भी पढ़े लिखे मुस्लिम थे, कायदे आज़म तो वे राजनैतिक मजबूरी के तहत बने थे. वैसे भी जीवन के संध्या काल में वे टी.बी. के दौर से गुज़र रहे थे. यदि उन्हें राष्ट्रपति, जवाहरलाल नेहरू या सरदार पटेल में से किसी एक को प्रधान मंत्री एवं बाबा साहब को गृह मंत्री बनाने की एक राय बन जाती तो तब शायद न तो देश टूटता और न जातिवाद हमारे प्रजातंत्र हावी हो पाता. दरअसल उनका पूरा जीवन सिद्धांतों के लिये संघर्ष की साक्षात मिसाल है जिसे उन्होंने ताउम्र तमाम तकलीफों के बावजूद सहर्ष स्वीकारा और शिद्दत के साथ निभाया. बकलम दुष्यंत -

चट्टानों पर खड़ा हुआ तो छाप रह गई पांवों की
सोचो कितना बोझ उठाकर मैं इन राहों से गुजरा

बाबा साहब ने हिंदु समाज के संदर्भ में जो विचार प्रकट किये उनसे सिद्ध होता है कि कि वे जाति प्रथा और छूआछूत जैसी परंपराओं से आहत होने के बावजूद हिंदु संस्कृति की राष्ट्रीय प्रतिबद्धता के प्रति अधिक आश्वस्त थे. जो निष्कर्ष निकाले वे संकेत देते हैं कि वे एक तरह से प्रोटेस्टेंट हिंदु ही थे. जीवन के अंतिम समय में बौद्ध धर्म गृहण करना भी मुख्य धारा में बने रहकर चेतावनी देने का उनका एक साहसिक प्रयास था.

भारत रत्न तो वे जन्मजात थे. यह अलंकरण उन्हें आज़ादी के कितने दशक पश्चात प्रदान किया गया. क्या विडंबना है. जिस शख्स ने देशवासियों को जीवन जीने की एक संपूर्ण आचार पद्धति याने देश का संविधान दिया उसे मात्र आभिजात्य कुल में पैदा न हो पाने की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी. वैसे यह भी शाश्वत सत्य है कि बाबा साहब ऐसे किसी सम्मान के मोहताज थे भी नहीं. उनका व्यक्तित्व तो इससे कई गुना ऊपर था. दरअसल अंबेडकर एक व्यक्ति नहीं विचार थे और विचार कभी मरा नहीं करता. कुछ समय के लिये भले ही वह बादलों की ओट में ढंक जाये, लेकिन समय के साथ उसका पुनः प्रादुर्भाव होता है और तब हर आगत पीढ़ी उससे प्रेरणा प्राप्त कर देश एवं समाज के लिये प्रगति के मार्ग की ध्वज वाहक बन कर उभरती है. आज वे होते तो शायद यही गुनगुनाते जो यहां उद्धृत है, अस्तु आईये पावन पलों में हम उनके अधूरे मिशन को अमली जामा पहनाने के प्रयास का पहला कदम बनें

है बहुत अंधियार कुछ जलती मशालें ले चलें.
बंद पर्वत की गुफाओं में उजाले ले चलें
अपने सारे ख्वाब उन मजलूमों में ही बांट दें
और अपने साथ उनके ज़ख्म, छाले ले चलें.

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्पलेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
वरिष्ठ संपादक
पंकज शुक्ला
प्रबंध संपादक
अरुण पटेल
(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2003/ 10923,
Ph. No. 0755-2422692, 4059111
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

वीवीआईपी कल्चर से देश पंचर

व्यंग्य

सूर्यदीप कुशवाहा

लेखक व्यंग्यकार हैं।

लोकतंत्र का सीधा अर्थ है–जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन। इसमें संविधान की नज़र में हर नागरिक बराबर है। लेकिन भारत में सदियों से चली आ रही सामंती सोच ने आज वीआईपी कल्चर का रूप ले लिया है। यह व्यवस्था समाज में खास और आम की एक गहरी और अदृश्य दीवार खड़ी करती है, जो हमारे बढ़ते देश के समानता के पहियों को पंचर कर रही है। हमारे देश में दो ही चीजें सबसे ज्यादा चमकती है एक नेताओं की गाड़ियां और दूसरा आम आदमी का टकला, जो इनकी सेवा में बाल उड़ा चुका है। इस देश को दुश्मनों से उतना खतरा नहीं है, जितना इस वीवीआईपी कल्चर से है। यह वो दीमक है जो सिस्टम को चाट रहा है और जनता को अंगूठा दिखा रहा है।

हवाई अड्डों से लेकर मंदिरों के गर्भगृह तक, हर जगह इस वीवीआईपी कल्चर ने अपने पैर पसार रखे हैं। भगवान के दर्शन करने हों तो आम आदमी घंटों लाइन में धक्का खाता है। उधर, हमारे वीवीआईपी साहब सीधे वीआईपी गेट से शॉर्टकट लेकर भगवान से हाथ मिलाकर आ जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे भगवान से मिलने के लिए भी आधार कार्ड नहीं, बल्कि 'विशिष्ट पहचान पत्र' की जरूरत होती है।

हवाई अड्डे पर हम अपनी चप्पलें और बेल्ट उतारकर सुरक्षा जांच करा रहे होते हैं। वहीं, वीवीआईपी महोदय अपनी भारी-भरकम सुरक्षा के साथ बिना किसी रोक-टोक के विमान की तरफ बढ़ जाते हैं। उनके लिए नियम नहीं बने हैं, बल्कि वे नियमों के ऊपर बने हैं। यह कल्चर देश की रगों में दौड़ रहे उस जहर की तरह है, जो धीरे-धीरे बराबरी के अहसास को ही खत्म कर रहा है।

यह वीवीआईपी कल्चर हमारे लोकतंत्र के टायर को लगातार पंचर कर रहा है। जनता के पैसे से पलने वाले ये नुमाइंदे जब खुद को जनता से ऊपर समझने लगते हैं, तो लोकतंत्र का मूल ढांचा ही चरमरा जाता है। पुलिस प्रशासन, जो जनता की सुरक्षा के लिए है, उसका आधा वक्त तो इन खास लोगों की जी-हुजूरी और एस्कॉर्ट करने में ही निकल जाता है।

जब तक सड़कें सबके लिए एक जैसी नहीं होंगी, जब तक अस्पतालों में इलाज सिफारिश के आधार पर मिलता रहेगा, तब तक हम एक विकसित राष्ट्र बनने का सिर्फ सपना ही देख सकते हैं। असली विकास तब होगा जब वीवीआईपी कल्चर का यह गुब्बारा फूटेगा और हर नागरिक को बराबरी का हक और सम्मान मिलेगा। आप एम्बुलेंस में जिंदगी और मौत से लड़ रहे हों या किसी जरूरी इंटरव्यू के लिए लेट हो रहे हों, इससे सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक 'साहब' का काफिला नहीं गुजरेगा, तब तक पहिए थम ही रहेंगे। लाल बत्ती भले ही गाड़ियों से उतर गई हो, लेकिन दिमागों में आज भी वैसी ही जल रही है। सायरन की वह तीखी आवाज आम आदमी को याद दिलाती रहती है कि तुम सिर्फ एक वोटर हो, प्रमोटर नहीं।

जब तक जनता इन स्वयंभू माननीयों को कुर्सी से उतारकर जमीन पर नहीं चलना सिखाएगी, तब तक यह देश ऐसे ही पंचर होकर घिसटता रहेगा। चमचों की फौज तैयार करने वाले ये नेता भूल जाते हैं कि लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, नौकर नहीं।

संघ की शाखा में बाबा साहब डॉ. अंबेडकर

पुणे में आयोजित संघ शिक्षा वर्ग में 525 स्वयंसेवक संघ कार्य का प्रशिक्षण ले रहे थे। स्वाभाविक ही डॉ. अंबेडकर ने जानना चाहा कि हिन्दू समाज के संगठन के लिए कार्य कर रहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इन 525 कार्यकर्ताओं में अस्पृश्य समुदाय के कितने लोग हैं। कतारबद्ध स्वयंसेवकों के बीच से गुजरने के बाद भी जब बाबा साहब यह पहचान नहीं कर सके कि अस्पृश्य वर्ग के बंधु कौन और कितने हैं? तब डॉ. हेडगेवार ने उनसे आग्रह किया कि वे स्वयं ही स्वयंसेवकों से यह पूछ लें। इसके बाद, जब डॉ. अम्बेडकर ने कहा कि 'जो अस्पृश्य हों, वे एक कदम आगे आएं', तो एक भी स्वयंसेवक आगे नहीं आया। इस पर बाबा साहब ने कहा, 'वे तो पहले ही ऐसा कहते थे कि आरएसएस में अस्पृश्य समाज के बंधु नहीं हैं'। तब डॉ. हेडगेवार ने स्पष्ट किया कि संघ में किसी को भी अस्पृश्य होने का अनुभव ही नहीं कराया जाता। उन्होंने डॉ. अम्बेडकर को सुझाव दिया कि यदि वे चाहें तो उपजातियों का नाम लेकर पूछ सकते हैं। इसके बाद डॉ. अम्बेडकर ने कहा, 'इस शिविर में जो चमार, महार, मांग, मेहतर हों, वे एक-एक कदम आगे आएं'। यह सुनते ही लगभग सौ स्वयंसेवक तुरंत एक साथ आगे आ गए। यह सब देखकर बाबा साहब को स्पष्ट हो गया कि सामाजिक समरसता के लिए संघ के प्रयास बहुत प्रभावी हैं।

अंबेडकर जयंती पर विशेष

डॉ. लोकेन्द्र सिंह

लेखक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक हैं।

सामाजिक समरसता के अग्रदूत बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर आशान्वित थे। उन्हें विश्वास था कि संघ हिन्दू समाज में एकजुटता और सामाजिक समरसता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। बाबा साहब डॉ. अंबेडकर संघ की शाखा और शिक्षा वर्ग में पहुँचकर एवं संघ के कार्यकर्ताओं से संवाद कर अपने विचार की पुष्टि करते रहे। डॉ. अंबेडकर का संघ के साथ पहला महत्वपूर्ण संपर्क 1935 में हुआ, जब वे पुणे में आयोजित संघ शिक्षा वर्ग के सायंकालीन बौद्धिक सत्र में आए थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात आद्य सरसंघचालक डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार से हुई। इस वर्ग में उन्हें जो अनुभूति हुई, उससे संघ के प्रति अपनत्व का भाव बन गया, जो उनके मन में जीवनपर्यंत बना रहा है। संघ के साथ संपर्क-संवाद भी बना रहा।

पुणे में आयोजित संघ शिक्षा वर्ग में 525 स्वयंसेवक संघ कार्य का प्रशिक्षण ले रहे थे। स्वाभाविक ही डॉ. अंबेडकर ने जानना चाहा कि हिन्दू समाज के संगठन के लिए कार्य कर रहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इन 525 कार्यकर्ताओं में अस्पृश्य समुदाय के कितने लोग हैं। कतारबद्ध स्वयंसेवकों के बीच से गुजरने के बाद भी जब बाबा साहब यह पहचान नहीं कर सके कि अस्पृश्य वर्ग के बंधु कौन और कितने हैं? तब डॉ. हेडगेवार ने उनसे आग्रह किया कि वे स्वयं ही स्वयंसेवकों से यह पूछ लें। इसके बाद, जब डॉ. अम्बेडकर ने कहा कि 'जो अस्पृश्य हों, वे एक कदम आगे आएं', तो एक भी स्वयंसेवक आगे नहीं आया। इस पर बाबा साहब ने कहा, 'वे तो पहले ही ऐसा कहते थे कि आरएसएस में अस्पृश्य समाज के बंधु नहीं हैं'। तब डॉ. हेडगेवार ने स्पष्ट किया कि संघ में किसी को भी अस्पृश्य होने का अनुभव ही नहीं कराया जाता। उन्होंने डॉ. अम्बेडकर को सुझाव दिया कि यदि वे चाहें तो उपजातियों का नाम लेकर पूछ सकते हैं। इसके बाद डॉ. अम्बेडकर ने कहा, 'इस शिविर में जो चमार, महार, मांग, मेहतर हों, वे एक-एक कदम आगे आएं'। यह सुनते ही लगभग सौ स्वयंसेवक तुरंत एक साथ आगे आ गए। यह सब देखकर बाबा साहब को स्पष्ट हो गया कि सामाजिक समरसता के लिए संघ के प्रयास बहुत प्रभावी हैं।

बाबा साहब डॉ. अंबेडकर से जुड़े रहे पूर्व लोकसभा सांसद बालासाहेब सालुंके ने भी बाबा साहब डॉ. अंबेडकर और संघ के संस्थापक डॉ. हेडगेवार की मुलाकात का उल्लेख किया है। उनके पुत्र काश्यप सालुंके ने भानुदास गायकवाड़ के साथ मिलकर बालासाहेब सालुंके के संस्मरणों एवं विचारों का संकलन किया है- 'आमचं सायेब : दिवंगत खासदार बालासाहेब सालुंके'। इस पुस्तक के पृष्ठ 25 और 53 पर डॉ. अंबेडकर और आएसएस के संदर्भ में उपरोक्त उल्लेख आते हैं। याद रहे कि बाला साहेब सालुंके और उनके पुत्र काश्यप सालुंके का संघ से कोई संबंध नहीं है। पुस्तक में बाला साहेब सालुंके के हवाले से लिखा गया है- 'पुणे में भाऊसाहेब गडकरी के बंगले पर डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉ. हेडगेवार की मुलाकात हुई। फिर भाऊसाहेब अभ्यंकर, श्री बाळासाहेब साळुंके के साथ बाबा साहब डॉ. अंबेडकर को भावे स्कूल में लगे स्वयंसेवकों के ग्रीष्मकालीन शिविर में भेंट के लिए ले गए। बाबा साहब ने यहाँ सैन्य अनुशासन और संगठन पर भाषण दिया'।

संघ की शाखा एवं संघ शिक्षा वर्ग में बाबा साहब के आने और भाषण देने का उल्लेख दत्तोपंत ठेंगडी ने अपनी पुस्तक 'एकात्मता के पुजारी- डॉ. बाबा साहब अंबेडकर' में भी किया है। उन्होंने लिखा है कि सन् 1937 में करहाड शाखा (महाराष्ट्र) के विजयादशमी उत्सव पर बाबा साहब का भाषण हुआ। सन् 1940 में बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर पुणे में संघ की शाखा में भी गए थे। यहाँ स्वयंसेवकों के समक्ष अपने विचार प्रकट किए। विश्व संवाद केंद्र, विदर्भ ने 9 जनवरी 1940 को प्रकाशित प्रसिद्ध मराठी दैनिक समाचारपत्र 'केसरी' की प्रति साझा की है। जिसके अनुसार, बाबा साहब डॉ. अंबेडकर 2 जनवरी, 1940 को सतारा जिले के करहाड गाँव स्थिति भवानी शाखा में गए। जहाँ स्वयंसेवकों से संवाद करते हुए उन्होंने कहा- 'कुछ बातों पर मतभेद हो सकते हैं। लेकिन संघ की तरफ अपनत्व की भावना से देखता हूँ'। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि इस ऐतिहासिक घटना की स्मृति में 2 जनवरी, 2025 को लोक कल्याण मंडल न्यास की ओर से श्री भवानी संघ स्थान पर बंधुता परिषद नाम से एक वैचारिक कार्यक्रम किया गया। इस आयोजन में अंबेडकरवादी संगठन के नेता शामिल हुए और अपने विचार भी प्रकट किए।

शाखा और वर्ग के बाहर भी डॉ. अंबेडकर का संपर्क संघ के कार्यकर्ताओं के साथ रहा। महात्मा गांधी की हत्या के झूठे आरोप लगाकर जब संघ को कुचलने का प्रयास किया गया, जब द्वितीय सरसंघचालक माधव सदाशिवराव गोलवलकर उपाख्य 'श्रीगुरुजी' संघ से प्रतिबंध हटाने के लिए प्रयास कर रहे थे। इस क्रम में सितंबर-1949 में दिल्ली में डॉ. अंबेडकर की मुलाकात श्रीगुरुजी से हुई। दत्तोपंत ठेंगड़ी की पुस्तक 'डॉ. अम्बेडकर और सामाजिक क्रांति की यात्रा' में इस मुलाकात का उल्लेख मिलता है। इसके साथ ही, धनञ्जय कीर ने अपनी पुस्तक 'डॉ. अम्बेडकर : लाइफ एंड मिशन' में भी इस मुलाकात का उल्लेख किया है। हालांकि, दोनों ने इस बात का कोई संकेत नहीं दिया कि उनमें क्या बातचीत हुई थी। लेकिन यह स्पष्ट किया है कि यह मुलाकात संघ पर लगे प्रतिबंध को हटाने के प्रयासों के संदर्भ में थी।

बाबा साहब डॉ. अंबेडकर के प्रति संघ में सदैव सम्मान का भाव रहा है। संघ ने अपने एकात्मता स्रोत (पूर्व में जिसे प्रातः स्मरण कहते थे) में भी बाबा साहब को भी शामिल किया है। अर्थात् संघ के लिए बाबा साहेब प्रातः स्मरणीय और राष्ट्रीय एकात्मता को पुष्ट करनेवाले महापुरुष हैं। एकात्मता स्रोत का पाठ करते समय स्वयंसेवक बाबा साहेब के कृतित्व एवं व्यक्तित्व का स्मरण कर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं। इस विजयादशमी के उत्सव पर सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत जी ने भी अपने उद्बोधन में बाबा साहब डॉ. अंबेडकर का स्मरण किया। अपने उद्बोधन में समाज की एकता पर बात रखते हुए सरसंघचालक जी ने कहा कि 'हमारी इस एकता के आधार को डॉ. अम्बेडकर साहब ने अन्तर्निहित सांस्कृतिक एकता कहा है'।

अंबेडकर, जगजीवन और कांशीराम किसके नायक

यूपी के चुनाव में जातीय समीकरणों को साधने के लिए सियासी दल बिसात बिछा रहे हैं। राज्य में 21 प्रतिशत दलितों को अपने-अपने प्रभाव में लाने के लिए होड़ लगी है। संविधान निर्माता डॉ. अंबेडकर, पूर्व रक्षा मंत्री जगजीवन राम और बसपा संस्थापक कांशीराम के नाम के सहारे सियासत साधने की जबरदस्त होड़ लगी है।

विशेष : अंबेडकर जयंती

वेद विलास उनियाल

(वरिष्ठ पत्रकार, समीक्षक)

संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर के नाम पर खासी खींचतान दिखती है। बसपा हर बार 14 अप्रैल को बड़े स्तर पर अंबेडकर जयंती मनाती रही है। सपा और उनके नेता अखिलेश पीडीए का नारा जरूर देते रहे हैं लेकिन उन्हें आभास रहा है कि पीडीए में उनके लिए सबसे कमजोर कड़ी दलित वर्ग रहा है। यह वर्ग सपा से तब कुछ हद तक जुड़ पाया जब सपा के साथ बसपा या कांग्रेस का गठबंधन रहा हो। इस बार सपा नेता अखिलेश ने दलित वर्ग को साधने के लिए डॉ अंबेडकर के नाम पर राज्य भर में कार्यक्रम किए। वह लोहियावाद के साथ अंबेडकरवाद को जोड़कर एक धुरी तैयार कर रहे हैं। सपा ने कांशीराम की जयंती को पीडीए दिवस के रूप में मनाना शुरू कर दिया है। मुस्लिम मतों पर उनको भरोसा है।

सपा अंबेडकर के साथ-साथ दलित वर्ग के नायक और संस्थापक कांशीराम के नाम को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है। यहां कांशीराम किसके इसलिए दोनों पार्टियों में जमकर संघर्ष हो रहा है। सपा नेता मान रहे है कि कांशीराम से जुड़ाव दिखाकर वह दलित वर्ग से सहानुभूति अर्जित कर सकते हैं। हालांकि, 2023 में भी अखिलेश ने रायबरेली में कांशीराम की प्रतिमा का अनावरण किया था। लेकिन लोकसभा चुनाव में कथित संविधान बचाओ का नारा सपा के अनुकूल रहा उससे पार्टी ने कांशीराम की जयंती को पीडीए दिवस मनाने का निर्णय लिया। पीडीए के फार्मूले पर चलते हुए वह अपनी जनसभा में लोगों को याद दिलाने की कोशिश करते हैं कि कांशीराम और मुलायम सिंह ने यूपी में 1993 में हाथ मिलाकर राज्य की राजनीति की धारा बदली थी।

बसपा मानती है कि डॉ भीमराव अंबेडकर के सामाजिक न्याय के सिद्धांत पर चलने वाली वह प्रमुख पार्टी हैं। बसपा के संस्थापक होने के नाते वह कांशीराम पर अपना पूर्ण अधिकार जताती है। इसलिए सपा की ऐसी कोशिशों पर विराम लगाते हुए बसपा प्रमुख मायावती ने टिप्पणी की थी कि सपा ने कांशीराम के नाम पर जिले का नाम बदल दिया था। वह यह लखनऊ गेस्ट हाउस कांड की याद दिलाना नहीं भूलती। बसपा मानती रही है कि उसके वोट तो सपा के लिए ट्रांसफर हुए लेकिन सपा से उसके उम्मीदवारों को कोई मदद नहीं मिली। नायकों को खींचने का संघर्ष यूपी की राजनीति को दिलचस्प बनाया है। 1987 तक यूपी के दलित कांग्रेस से जुड़े रहे। उसका बड़ा आधार मुस्लिम दलित बने रहे। राज्य के सियासी हालात बदले और कांग्रेस ने यूपी में दलित आधार को खो दिया।

कांग्रेस इसी लिए अपने दलित आधार को पाने के लिए डॉ अम्बेडकर बाबू जगजीवन राम और कांशीराम का स्मरण कर रही हैं। वह अहसास करा रही है कि नेहरू के पहले मंत्रिमंडल में जगजीवन राम को मंत्री बनाया गया था। अब कांग्रेस अंबेडकर को संविधान निर्माता के रूप में प्रस्तुत कर रही है और यह जताना नहीं भूलती कि अंबेडकर नेहरू के पहले मंत्रिमंडल में शामिल हुए। राहुल गांधी ने दलितों से जुड़ाव दिखाते हुए कहा कि अगर नेहरू जीवित होते तो कांशीराम को यूपी का सीएम बना दिए होता। कांग्रेस नेता राहुल गांधी संविधान की प्रति दिखाकर दलित मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश करते रहे हैं।

कांग्रेस ने बसपा को यह संकेत भी दिए थे कि वह उसके साथ गठबंधन करके यूपी में राजनीति को नया मोड़ दे सकती है। कांग्रेस एक बार बसपा के साथ समझौता कर चुकी है। लेकिन बसपा ने अब अकेले चलने की रणनीति बनाई है । बसपा कांग्रेस को भी आड़े हाथ लेने से नहीं चूकती। बसपा नेता मायावती ने कांग्रेस पर तीखे प्रहार करते हुए कहा है कि कांग्रेस ने अंबेडकर को हमेशा हाशिए पर रखा। कांग्रेस ने अपने लंबे शासन काल में दलित वर्ग के लिए आरक्षित पदों को ईमानदारी से नहीं भरा। बसपा मतदाताओं से संवाद कर रही है कि कांग्रेस ने पूरे जीवन बाबा साहब की उपेक्षा की अब वह कांशीराम के नाम पर राजनीति कर रही है।

यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने दलित वर्ग को प्रभाव में लेने के लिए इस बात पर फोकस किया है कि उसकी डबल इंजन सरकार में आर्थिक योजनाओं का लाभ हर वर्ग को मिला है। राज्य में कानून व्यवस्था बेहतर हुई है। भाजपा दावा करती है कि योगी राज में दलितों पर अत्याचार की घटनाएं सुनने को नहीं मिलती। वह बसपा की तरह कांग्रेस को घेरती है कि देश के पहले उपचुनाव में कांग्रेस ने डॉ अंबेडकर को उत्तर मुंबई की सीट पर हराने के लिए हर तरह की रणनीति अपनाई। कांग्रेस ने एक परिवार के तीन लोगों को तो भारत रत्न दिया लेकिन दशकों बाद भी बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न नहीं दिया गया। बीजेपी बाबू जगजीवन राम को लेकर भी कांग्रेस को आड़े हाथ ले रही है। बीजेपी अहसास करा रही है कि कांग्रेस ने 1971 के युद्ध की सफलता का श्रेय बाबू जगजीवन राम को नहीं दिया।

कैसे याद करें अम्बेडकर को?

आजादी के आन्दोलन के दौरान हो रहे सामाजिक सुधार के रचनात्मक काम और बाद में भारत के संवैधानिक मूल्यों के अनुसार समतावादी समाज बनाने के जवाहरलाल नेहरू के जतन और डॉ. राममनोहर लोहिया के जाति तोड़ो आन्दोलन ने जाति पांति के मकड़जाल से समाज को निकालने की कोशिशें की थीं। इन कोशिशों के असर भी हुए जिसके कारण जलालत भरी जिन्दगी जीने वाली जाति के लोगों को कुछ राहत मिली। यद्यपि यह राहत केवल उन्हीं तक सीमित रही जो अपनी जड़ों को छोड़कर,पढ़ लिख कर और अपना जातिगत व्यवसाय या पेशा न कर दूसरे व्यवसाय को अपना कर कहीं दूर जा बसे। जो कहीं नहीं जा सके और अपने गांवों में ही रह कर अपना जातिगत व्यवसाय ही कर रहे हैं वे जात-पांत के ऊंच-नीच के जाल में फंसे रहकर नर्क भोग रहे हैं।

जयंती पर विशेष

श्याम बोहरे

लेखक सामाजिक कार्यकर्ता हैं।

इससे अधिक आश्चर्य की बात और क्या हो सकती है कि दलित (जिन्हें पहले हरिजन कहा जाता था) अछूत होते हुए भी हिन्दू हैं! मानव जाति के ये लोग क्यों हिन्दू बने रहने के लिए अभिशप्त हैं? यह समझ पाना कोई आसान काम नहीं हो सकता, लेकिन यह समझ में जरूर आता है कि भीमराव अम्बेडकर ने हिन्दु धर्म रहते हुए अपमान और जलालत भरी जिन्दगी से आजाद होने के लिए हिन्दू धर्म छोड़ने का साहसिक और ऐतिहासिक कदम क्यों उठाया? आज अम्बेडकर होते तो हिन्दू धर्म के पाखण्ड और जलालत भरे जीवन से आजादी की बात कहने के लिए उन्हें राष्ट्रद्रोही घोषित कर दिया होता। आजादी के आन्दोलन के दौरान हो रहे सामाजिक सुधार के रचनात्मक काम और बाद में भारत के संवैधानिक मूल्यों के अनुसार समतावादी समाज बनाने के जवाहरलाल नेहरू के जतन और डॉ. राममनोहर लोहिया के जाति तोड़ो आन्दोलन ने जाति पांति के मकड़जाल से समाज को निकालने की कोशिशें की थीं। इन कोशिशों के असर भी हुए जिसके कारण जलालत भरी जिन्दगी जीने वाली जाति के लोगों को कुछ राहत मिली। यद्यपि यह राहत केवल उन्हीं तक सीमित रही जो अपनी जड़ों को छोड़कर,पढ़ लिख कर और अपना जातिगत व्यवसाय या पेशा न कर दूसरे व्यवसाय को अपना कर कहीं दूर जा बसे। जो कहीं नहीं जा सके और अपने गांवों में ही रह कर अपना जातिगत व्यवसाय ही कर रहे हैं वे जात-पांत के ऊंच-नीच के जाल में फंसे रहकर नर्क भोग रहे हैं। पढ़ाई लिखाई का विस्तार होने, सामाजिक जागरूकता के अनेकों कार्यक्रमों, बढ़ते हुए औद्योगिकीकरण और शहरीकरण की वजह से दूर दराज आने जाने के कारण जातिगत भेदभाव और उंचनीच के व्यवहार में अन्तर आए हैं जो सकारात्मक संकेत हैं। कांग्रेसियों, समाजवादियों, वामपंथियों और अन्य प्रगतिशील शक्तियों की असफलता के कारण हिन्दु राष्ट्र के पैरोकारों की सरकार सत्ता में आई जिससे जातिविहीन और समतावादी समाज को गहरा झटका लगा है। आज सरकार के चाल चरित्र और चेहरे से ऐसा महसूस हो रहा है कि समय का पहिया फिर वहीं पीछे ले जाने की कोशिश हो रही है जहां अम्बेडकर हिन्दू धर्म छोड़ने पर मजबूर हुए थे। पहले ज्ञान अर्जित (वेद पाठ) करने के 'अपराध' में राजा राम के द्वारा शम्बूक वध किया गया, कौशल हासिल करने वाले एकलव्य को अंगूठा काटकर देने पर मजबूर किया गया तो आज सत्ताधारी दल के नेताओं के सक्रिय हस्तक्षेप से हैदराबाद केन्द्रीय विश्वविद्यालय में दलित छात्रों की क्षात्रवृत्ति रोकी जा रही है, उन्हें छात्रावास से निकाल कर प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसके कारण प्रतिभाशाली शोध छात्र रोहित वेमूला आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। दलित प्रताड़ना के तरीके को छोड़ कर और क्या बदला है आज? एक विष्वविद्यालय में बौद्धिक विचार विमर्ष के लिए बने अम्बेडकर पेरियार स्टडी सर्कल की मान्यता रद्द की जाती है, दलित क्षात्रों के वजीफे रोक लिए जाते हैं, उन्हें विश्वविद्यालय परिसर से बेदखल करके ज्ञान हासिल करने से वंचित किया जाता है। क्यों अम्बेडकर आज भी इतने खतरनाक नजर आते हैं इस निजाम को आज सरकार अम्बेडकर की मूर्ति लगायेगी,समारोह मनायेगी, भवन एवं संस्थानों के नाम उनके नाम पर रखेगी, विज्ञापन देकर बाबा साहब के साथ-साथ लगे हाथ अपनी और अपने राजनेताओं की छबि चमकायेगी, दिखावे के सभी अनुष्ठान करेगी। लेकिन ज्यों ही दलित समाज के लोग अम्बेडकर का दिखाया रास्ता अख्तयार करेंगे मतलब 'शिक्षित होंगे,संगठित होंगे और संघर्ष करेंगे तो फिर उन्हें रोहित वेमूला की जगह पहुंचाएगी। आज सवाल यह है कि अम्बेडकर को याद करने का तरीका क्या हो? डॉ. अम्बेडकर जयंती के अवसर पर भव्य समारोह, किराये की भीड़, बाबा साहब की भक्ति का भौंडा प्रदर्शन, लफ्फाजी भरे भाषण, भवनों के नामकरण आदि के लालीपाप में ही भरमाकर केवल वोट बैंक में सीमित हो जाना। या फिर शिक्षित और संगठित होकर संघर्ष के जरिए मानवीय, न्यायपूर्ण, धर्मरिपेक्ष्य और समतावादी समाज के लिए कोशिशें की जायें जहां किसी शैक्षिक परिसर में विचार विमर्श का गला न घोंटा जा सके, किसी रोहित वेमूला को मरने के लिए मजबूर न किया जा सके, किसी कन्हैया को भूख से आजादी गरीबी से आजादी, संघवाद से आजादी की बात कहने पर राष्ट्रद्रोही करार कर जेल में न ठूंसा जा सके। संकीर्ण राष्ट्रवाद की सीमाओं को लांघकर भारत के संविधान की उद्देशिका में व्यक्त संकल्प का समाज बनाने के लिए आन्दोलन। अम्बेडकर ने केवल दलित समाज के हितों के लिए काम नहीं किया, उनका काम व्यापक समाज को मानवीय,समतावादी और न्यायपूर्ण बनाने के लिए था इसलिए उन्हें केवल दलितों का मसीहा मानना उनके महत्वपूर्ण सामाजिक अवदान की अवहेलना होगी।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम से देश की आधी आबादी को मिलेगा न्याय

नारी शक्ति वंदन अधिनियम - महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम : केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर

धार। केंद्रीय राज्य मंत्री भारत सरकार सावित्री ठाकुर ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को देश की महिलाओं के लिए एक ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी पहल बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में यह अधिनियम महिलाओं को सशक्त, आत्मनिर्भर और निर्णय लेने में सहभागी बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर है।

प्रेस वार्ता में धार विधायक नीना वर्मा, भाजपा जिला उपाध्यक्ष राखी राय,महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष कुसुम सोलंकी, जिला पंचायत सदस्य गायत्री पुरोहित, मोर्चा जिला महामंत्री सुनिता दुबे मंचासीन रहे ।

सावित्री ठाकुर जी ने अपने उद्बोधन में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए लगातार ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जनधन योजना, मातृत्व अवकाश में वृद्धि जैसे अनेक कदमों से महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। इस अधिनियम के माध्यम से संसद एवं राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 33 प्रतिशत तक आरक्षण प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। यह केवल एक कानूनी प्रावधान नहीं, बल्कि देश की करोड़ों माताओं-बहनों के सम्मान, अधिकार और भागीदारी को सुनिश्चित करने का संकल्प है।

उन्होंने कहा कि विगत वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण को केंद्र में रखते हुए अनेक योजनाएं लागू की गई हैं। उज्ज्वला योजना के माध्यम से करोड़ों महिलाओं को धुएं से मुक्ति मिली, जनधन खातों के जरिए आर्थिक सशक्तिकरण हुआ, और मुद्रा योजना से महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्राप्त हुए। इसके साथ ही 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' अभियान ने समाज में बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच विकसित की है। श्रीमती ठाकुर ने यह भी उल्लेख किया कि महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सरकार ने मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह किया, जिससे कार्यरत महिलाओं को सम्मानजनक वातावरण मिला।

आज देश में महिलाओं की भागीदारी विज्ञान, तकनीक, शिक्षा और प्रशासन के हर क्षेत्र में निरंतर बढ़ रही है, जो एक विकसित भारत की नींव को मजबूत कर रही है।

उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम केवल वर्तमान को नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सशक्त बनाने का माध्यम है। यह अधिनियम महिलाओं को नीति निर्माण में अधिक अवसर प्रदान करेगा और देश के लोकतंत्र को और अधिक मजबूत बनाएगा।

अंत में, श्रीमती ठाकुर ने विश्वास व्यक्त किया कि यह ऐतिहासिक कदम भारत को महिला-नेतृत्व वाले विकास मॉडल की ओर अग्रसर करेगा और देश की बेटियों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

'गांव - बस्ती चलो अभियान' के तहत बैलगाड़ी से पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल

सादगी और सहजता के साथ अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुंचने का संकल्प

बैतूल। 'गांव- बस्ती चलो अभियान' के अंतर्गत भाजपा प्रदेशाध्यक्ष व बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल ने रविवार को बैतूल, भैंसदेही एवं घोड़ाडोंगरी विधानसभा क्षेत्र के देवगांव, खाटापानी, चिरापाटला , मंडई ग्रामों का भ्रमण कर ग्रामीणों और कार्यकर्ताओं से भेंटकर वरिष्ठजनों को सम्मानित किया। इस दौरान श्री खंडेलवाल ने सार्वजनिक और धार्मिक स्थलों पर सफाई कर ग्रामीणों को स्वच्छता का संदेश भी दिया। उन्होंने भीमपुर में महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किए। गांव - बस्ती चलो अभियान के तहत भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने बैलगाड़ी से ग्राम चिरापाटला में अनोखे अंदाज में पहुंचकर सबको आश्चर्यचकित कर दिया। चिरापाटला ग्राम में बैलगाड़ी से सवार होकर बैलों को हांकते हुए पहुंचकर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष व बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल ने सादगी, परंपरा और ग्रामीण जीवन से उनके गहरे जुड़ाव का संदेश दिया। गांव - बस्ती में भ्रमण के दौरान ग्रामीणों ने पारंपरिक रीति -रिवाजों, तौर-तरीकों और ढोल नगाड़ों से उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान खंडेलवाल ने ग्रामीणों और कार्यकर्ताओं से सहजता के साथ भेंट कर उनकी समस्याएं सुनीं और संवाद किया।

गांव, गरीब, किसान और वंचित वर्ग का उत्थान हमारी प्राथमिकता- इस दौरान ग्रामीणों को संबोधित करते श्री खंडेलवाल ने कहा कि गांव बस्ती चलो अभियान का उद्देश्य समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचकर उसकी समस्याओं को समझना और समाधान हेतु ठोस पहल करना है। उन्होंने कहा कि भाजपा

की सोच हमेशा से गरीब, किसान और वंचित वर्ग के कल्याण पर केंद्रित रही है। उन्होंने आगे कहा कि सादगी और सहजता ही जनप्रतिनिधि की सबसे बड़ी ताकत होती है। श्री खंडेलवाल ने कार्यकर्ताओं से संगठन को मजबूत करने और सरकार की योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि गांव- गरीब, किसान और अंतिम पंक्ति के व्यक्ति का उत्थान ही हमारी प्राथमिकता है और इसी उद्देश्य के साथ भाजपा का हर कार्यकर्ता गांव-गांव तक पहुंच रहा है। इस दौरान भैंसदेही विधायक महेंद्र सिंह चौहान, घोड़ाडोंगरी विधायक गंगाबाई उईके, पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष बैतूल अनिल सिंह कुशवाह, गांव -बस्ती चलो अभियान के जिला संयोजक भाजपा जिला महामंत्री कृष्णा गायकी, पूर्व जनपद अध्यक्ष चिरौंजी पटेल, भाजपा अजजा मोर्चा जिला अध्यक्ष संतोष टेकाम, चिरापाटला मंडल अध्यक्ष राजेंद्र यादव सहित कार्यकर्ता व ग्रामीणजन मौजूद थे।

भाजपा कार्यालय देवास पर 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2026' विषय पर प्रेस वार्ता आयोजित

देवास। भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय देवास में 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2026' विषय पर एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता पूर्व भाजपा प्रदेश मंत्री अंजु माखीजा रहीं। साथ ही देवास विधायक गायत्री राजे पवार एवं भाजपा जिला अध्यक्ष डॉ. रायसिंह सेंधव ने भी प्रेस वार्ता को

संबोधित किया। मुख्य वक्ता अंजु माखीजा ने अपने संबोधन में कहा कि 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' केवल एक कानून नहीं, बल्कि देश की मातृशक्ति को सशक्त बनाने की ऐतिहासिक पहल है। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम महिलाओं को निर्णय लेने की मुख्यधारा में लाने का सशक्त माध्यम बनेगा। वर्षों से लंबित महिला आरक्षण का सपना अब साकार हुआ है, जिससे महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित होगी। यह कदम भारत के लोकतंत्र को और अधिक मजबूत बनाएगा। विधायक श्रीमती गायत्री राजे पवार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं को सम्मान, सुरक्षा और अवसर प्रदान करने की दिशा में निरंतर कार्य हो रहा है। 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' महिलाओं को 'मतदाता' से आगे बढ़ाकर 'निर्णायक' की भूमिका में स्थापित करेगा। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में महिलाएं देश की नीति-निर्माण प्रक्रिया में अग्रणी भूमिका निभाएंगी, जिससे समाज के हर वर्ग का समग्र विकास सुनिश्चित होगा। भाजपा जिला अध्यक्ष डॉ. रायसिंह सेंधव ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने दशकों तक महिला आरक्षण के नाम पर केवल राजनीति की, लेकिन उसे लागू करने का साहस नहीं दिखाया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने ठोस निर्णय लेते हुए महिलाओं को उनका अधिकार दिलाने का काम किया है। यह अधिनियम महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।

नवागत कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस, सुशासन और जवाबदेही पर रहेगा फोकस

बैतूल। नवागत कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे ने पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार मीडिया से रूबरू होते हुए प्रशासन की प्राथमिकताओं को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि जिले में गुड गवर्नेंस को जमीनी स्तर तक प्रभावी रूप से लागू करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते कलेक्टर डॉ. सोनवणे ने बताया कि अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जनसमस्याओं के निराकरण में पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता बरती जाए तथा हर शिकायत का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि वित्तीय अनियमितताओं और गड़बड़ी पर 'जीरो टॉलरेंस' की नीति अपनाई जाएगी और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत जल संरक्षण एवं संवर्धन के कार्यों को धरातल पर उपयोगी और टिकाऊ बनाने के निर्देश सभी सीएमओ एवं सीईओ को दिए गए हैं। तकनीकी विशेषज्ञों के परामर्श से जल संरचनाओं और निर्माण कार्यों को अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। राजस्व प्रकरणों के समय-सीमा में निराकरण पर विशेष जोर देते हुए कलेक्टर ने कहा कि आम नागरिकों को अनावश्यक परेशानी से बचाना प्रशासन की जिम्मेदारी है। इसके साथ ही स्वास्थ्य, कृषि और शिक्षा क्षेत्रों में मैदानी संस्थाओं को सुदृढ़ करने तथा विभिन्न विभागों के कार्यों का नियमित फील्ड निरीक्षण करने के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।

पत्रकार कल्याण परिषद ने किया नवागत कलेक्टर का स्वागत

बैतूल। जिले के नवागत कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे का भारत के पत्रकारों के राष्ट्रीय संगठन, पत्रकार कल्याण परिषद जिला इकाई बैतूल द्वारा पुष्प गुच्छ भेंटकर स्वागत एवं सम्मान किया गया। इस दौरान नवागत कलेक्टर श्री सोनवणे ने पत्रकार कल्याण परिषद

बैतूल के पदाधिकारियों से रूबरू होते हुए पत्रकारों एवं प्रशासन के बीच अच्छा समन्वय बनाने को प्राथमिकता देने की बात कही।

इस अवसर पर पत्रकार कल्याण परिषद के जिलाध्यक्ष कैलाश अग्निहोत्री, महासचिव संजय द्विवेदी, संभागीय प्रभारी राधेश्याम सिन्हा, उपाध्यक्ष विक्की लिल्हारे, सचिव चंद्रशेखर यादव सहित बडी संख्या में पत्रकार मौजूद थे। गौरतलब है कि कलेक्टर श्री सोनवणे ने रविवार को बैतूल पहुंचकर कलेक्टर का पदभार ग्रहण किया है। इसके पूर्व नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी बैतूल कलेक्टर थे, जिनका तबादला रीवा कलेक्टर के रूप में हुआ है।

सुशासन को जमीनी स्तर तक पहुंचाएं : कलेक्टर सोनवणे

वित्तीय अनियमितता पर रहेगा जीरो टॉलरेंस

बैतूल। नवागत कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में समय-सीमा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न शासकीय योजनाओं की समीक्षा करते हुए उन्होंने अधिकारियों को शासन की प्राथमिकताओं के अनुरूप कार्य करने के निर्देश दिए। कलेक्टर डॉ. सोनवणे ने कहा कि सभी अधिकारी अपने दायित्वों को भली-भांति समझें और योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि सुशासन को पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ जमीनी स्तर तक पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। आमजन की समस्याओं का निष्पक्ष एवं संवेदनशील समाधान किया जाना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि कोई भी प्रकरण लंबे समय तक लंबित न रहे। व्यवस्थित कार्ययोजना बनाकर उनका समयबद्ध निराकरण किया जाए। विशेष रूप से राजस्व एवं लोक सेवा गारंटी के मामलों को प्राथमिकता से निराकरण किया जाए। उन्होंने कहा कि आमजन को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अनावश्यक रूप से परेशान होना पड़े, यह बिल्कुल स्वीकार्य नहीं होगा। कलेक्टर डॉ सोनवणे ने अधिकारियों को अपने अधीनस्थ अमले पर प्रभावी नियंत्रण रखने के निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिए संबंधित अधिकारी भी जिम्मेदार होंगे। वित्तीय अनियमितताओं पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। साथ ही जनहित के कार्यों को अधिक प्रभावी बनाने हेतु समय-समय पर फीडबैक साझा करने के निर्देश दिए।

एसडीएम अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था सुदृढ़ करे- कलेक्टर डॉ. सोनवणे ने सभी एसडीएम को अपने-अपने क्षेत्रों में कानून-व्यवस्था सुदृढ़ रखने के निर्देश दिए। उन्होंने विभागीय समन्वय के साथ प्रकरणों का विवेकपूर्ण निराकरण करने, नियमित बैठकें आयोजित करने तथा क्षेत्रीय निरीक्षण सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

महान समाज सुधारक महात्मा फुले को किया याद

बैतूल। अंबेडकर शिक्षा महाविद्यालय में 11 अप्रैल को महान समाज सुधारक एवं नारी शिक्षा के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती को मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत महाविद्यालय के संचालक

इंजी. ध्रुवप्रकाश अग्रवाल एवं प्राचार्य डॉ. जी.डी. देशमुख द्वारा महात्मा फुले के छायाचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। डॉ देशमुख ने अपने उद्बोधन में कहा कि महात्मा फुले ने अपने जीवनकाल में शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। उनका मानना था कि ज्ञान सभी वर्गों के लिए समान हो, उन्होंने अपना जीवन गरीबों, वंचितों एवं कमजोर वर्गों को सम्मान दिलाने के लिए समर्पित कर दिया। उनकी पहली शिष्या उनकी धर्मपत्नी सावित्री बाई फुले थी, जो भारत की पहली महिला शिक्षिका थी। कार्यक्रम में बी.एड. स्टाफ एवं बी.एड. स्कालर्स उपस्थित रहें।

रानी पिपरिया में 12 दिनों से बिजली नदारद, आरोप पिछले दिनों के चक्काजाम की खुन्नस निकाल रहे हैं

सोहागपुर। ग्राम रानी पिपरिया में विगत 12 दिनों से पूरी हरिजन बस्ती के वाशिंदे बिजली से परेशान हैं। उन लोगों का जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। पानी के अभाव में नागरिक नहा ही नहीं पा रहे हैं। ऐसे में शिकायत करने विधुत विभाग कार्यालय में कुछ लोगों वहां के पानी के पाईप नहाकर संतोष तो जताया। वहीं सरकार की अफसरशाही पर कटाक्ष भी किया कि हम पानी के अभाव में हैं। यहां बिजली कार्यालय में पानी भरपूर है। कतिया समाज जिला मीडिया प्रभारी के पी सायलवार ने बताया कि ग्राम रानी पिपरिया के ग्रामीणों का बिजली के अभाव में जनजीवन बेहाल हो रहा है। विगत 12 दिनों से लगातार बिजली बंद पड़ी है। उसका कारण बताते कहा कि

17 मार्च 2026 को हरिजन बस्ती के ट्रांसफर पर से केवल पूरी हरिजन बस्ती में वगैर सूचना के विद्युत कनेक्शन काट दिया था। जिससे आक्रोशित गरीब ग्रामीणों, छात्र छात्राओं ने पिपरिया नर्मदापुरम राज्य मार्ग पर चक्काजाम कर दिया था। इसी बीच कांग्रेस नेता पुष्पराजसिंह पटेल कहीं जा रहे थे।जब पीड़ितों ने समस्याएं बताई तब वे चक्काजाम में शामिल होकर रास्ते पर बैठ गए। प्रदर्शन का असर यह हुआ था कि बिजली विभाग ने तुरंत बिजली काट गई बिजली कनेक्शन जोड़ दिए थे। वहीं ग्रामवासी उपभोक्ताओं ने यथा सामर्थ्य

के अनुसार बिल भी जमा कर दिया थे। लेकिन दो अप्रैल 2026से उसी हरिजन बस्ती की डी पी को खराब बताकर बिजली बंद कर दी गई। ग्रामीणों को भीषण गर्मी में पानी की एक बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। विगत दिवस के पी सायलवार के नेतृत्व में प्रत्येक घर से एक गरीब- ग्रामीण उपभोक्ता बिजली विभाग के आला अधिकारी से संपर्क करने बिजली विभाग के पिपरिया स्थित मंडल कार्यालय पहुंचा। उपमहाप्रबंधक डी श्री भदौरिया जी से अपनी व्यथा सुनाकर बिजली चालू करने का आग्रह किया। श्री सायलवार ने आरोप लगाया है कि डी साहब ने चक्काजाम निकाली। गई इसके साथ ही फोन पर किसी कर्मचारी को डी पी उतरवाकर आफिस लाने को आदेश दिए। वहीं कुछ लोग बिजली विभाग के प्रांगण में बह रही पानी की नली से ही अपनी प्यास बुझाने लगे । वहीं हफ्ते भर से पानी की किल्लत के चलते नहाने से वंचित ग्रामीण व्यर्थ बह रहे पानी से ही नहाने लगे। यह भी अजीब नजारा था। आपने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि जिस समाज के उत्थान की बातें करते हैं।उनकी

हरिजन बस्ती की बिजली बंद होने से जनजीवन अस्त-व्यस्त है ।पानी के अभाव में जन-धन, पशु-पक्षी और मानवीय जीवन खतरे में है। आप प्रदेश सरकार के मुखिया हैं। ग्रामीणों को राहत प्रदान कराए।

सोहागपुर ब्लाक में नहीं हो रही गेहूं की खरीदी, किसानों पर मुसीबत बिचोलियों की पौ बारह, कांग्रेस नेता मिले एसडीएम से

सोहागपुर। सोहागपुर विधानसभा के मुख्यालय में पूरे ब्लाक में नहीं हो रही गेहूं की खरीदी, किसानों पर मुसीबत, बिचोलियों व्यापारियों की पौ बारह। कांग्रेस नेताओं ने अनुविभागीय अधिकारी प्रियंका भल्लावी से इसी संदर्भ में एसडीएम कार्यालय में किसानों समस्याओं से अवगत कराया। वहीं समिति प्रबंधकों द्वारा की गई घोषणाओं को भी संज्ञान में बताया। इस अवसर पर कांग्रेस के सोहागपुर विधानसभा चुनाव प्रत्याशी रहे पुष्पराजसिंह पटेल, पूर्व नपाध्यक्ष संतोष मालवीय, पूर्व ब्लाक कांग्रेस अध्यक्ष आलोक जायसवाल, पूर्व ब्लाक कांग्रेस अध्यक्ष गजेन्द्र चौधरी वकील प्रांजल तिवारी, किसान नेता केशरीसिंह पटेल ,नीरज चौधरी, विक्रम रघुवंशी आदि उपस्थित थे। कांग्रेस नेता पुष्पराजसिंह पटेल ने एसडीएम को अवगत कराया कि मैंने माखन नगर एवं सोहागपुर ब्लाक के सोसायटी केन्द्रों का जायजा लिया। लेकिन कहीं भी गेहूं की खरीदी प्रारंभ नहीं हुई है। वहीं कई छोटे छोटे किसानों ने अपनी उपज खरीदी केन्द्रों पर

खरीदी की आशा में रख दी है। खरीदी नहीं होने के कारण वर्तमान में बरसात होने की संभावना से उनके करें पसीने की कमाई पर बट्टा लगने की संभावना है। वहीं आपने एसडीएम को अवगत कराया कि समिति प्रबंधकों ने मांग रखी है कि हम खुले मैदान में गेहूं की खरीदी नहीं करेंगे। इससे हमें भारी नुक्सान होने की संभावना है। बताया जाता है प्रमिति प्रबंधकों ने इस कारण भी बाहर खरीदी नहीं कर रहे हैं कि उनको 19 रूपये मजदूरी दी जा रही है। यदि समिति वेयरहाउस में गेहूं खरीदी करके रखवाती है तो इसकी मजदूरी 25 तक होने की संभावना है। वहीं बाहर खरीदी होने से गेहूं चोरी होने की संभावना है। इसलिए गेहूं खरीदी में विलंब हो रहा है। नेताओं ने एसडीएम को अवगत कराया कि सिवनी मालवा में समिति प्रबंधकों को वेयरहाउस में खरीदी करने की अनुमति दी गई है। सभी ने अनुविभागीय अधिकारी प्रियंका भल्लावी से तत्काल इस मामले में संज्ञान लेने का आग्रह किया है ताकि किसानों का अहित नहीं हो। अनुविभागीय अधिकारी प्रियंका भल्लावी ने इस प्रतिनिधि को बताया कि शासन की नीति के अनुसार सोहागपुर के केन्द्रों पर खरीदी प्रारंभ हो गई है। इस प्रतिनिधि मंडल के द्वारा साझा की गई अन्य समस्याओं को लेकर उच्च अधिकारियों को जानकारी देकर मार्गदर्शन लिया जाएगा। इधर पता चला कि बिचोलिए की गेहूं खरीदी नहीं होने के पौ बारह हो गई है।वे किसानों से अपनी मनमानी कीमतों पर गेहूं खरीदी कर रहे हैं।इधर किसानों को भी बरसात का डर सता रहा है।इस कारण किसान भी मजबूर हैं। इधर कुआं उधर खाई।

महाराष्ट्र समाज देवास में चुनाव संपन्न, दीपक कर्पे निर्विरोध अध्यक्ष चयनित

देवास। महाराष्ट्र समाज देवास में रविवार को आयोजित साधारण सभा और चुनाव प्रक्रिया ने समाज की एकजुटता और सक्रियता की मजबूत तस्वीर पेश की। लंबे समय बाद आयोजित इस बैठक में समाज के सदस्यों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी का परिचय दिया। साधारण सभा की शुरुआत समाज अध्यक्ष दीपक कर्पे एवं ट्रस्ट अध्यक्ष संजय कोटस्थाने द्वारा विधिवत सरस्वती पूजन के साथ की गई। इसके बाद साधारण सभा में समाज के विकास, गतिविधियों और भविष्य की योजनाओं को लेकर खुलकर चर्चा हुई। कई सदस्यों ने रचनात्मक सुझाव दिए, तो कई ने समाज की पूर्व कार्यकारणी से प्रश्न भी पूछे गए, जिनके समाधानकारक उत्तर दीपक कर्पे और मिलिंद वैद्य ने दिए। कार्यकारिणी कोषाध्यक्ष नीलिंद म्हाडगुत द्वारा आय-व्यय का विस्तृत लेखा-जोखा प्रस्तुत किया गया, जिसे सदस्यों ने ध्यानपूर्वक सुना। न्यास का बजट और लेखा प्रबंधक सदाशिव जोशी ने प्रस्तुत किया। कार्यकाल पूर्ण होने पर पुरानी कार्यकारिणी को भंग कर नई कार्यकारिणी के गठन की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। निर्वाचन अधिकारी उदय कस्तूरे, अशोक कुलकर्णी की निगरानी में पारदर्शिता के साथ चुनाव संपन्न कराए गए। अध्यक्ष पद पर दीपक कर्पे सहित तीन महिला सदस्य वृषाली आप्टे,दिव्या गोटी ,रुशाली विपट निर्विरोध चुनी गईं, जो समाज में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी का संकेत है। इसके बाद शेष कार्यकारिणी पदों के लिए मतदान कराया गया। भीषण गर्मी के बावजूद समाज के सदस्य बड़ी संख्या में मतदान केंद्र पहुंचे और अपने मताधिकार का उपयोग किया। चुनाव में संकेत सुपेकर, भूषण अत्रे, प्रवीण रायगांवकर, शेखर धोड़पकर, भालचंद्र बकोरे, विवेक जोशी, मंदार मुळे, नीलींद म्हाडगुत, विजयी घोषित किए गए। प्रकाश कोरडे,रवि अयाचित,विवेक बक्षी , दिलीप बाकरे,नचिकेत मनोहर, सारंग लोटे के सहयोग से पूरी चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण और अनुशासित माहौल में संपन्न हुई, जिसने महाराष्ट्र समाज की संगठित ताकत और सक्रियता को फिर से उजागर कर दिया। नई कार्यकारिणी के गठन के साथ ही समाज में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार देखने को आने वाले समय में मिलने वाला है।

बंगाल चुनाव से दूर ही रहेंगे इंदौरियां

पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव हो और प्रदेश के कद्दावर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की जिक्र न हो, ऐसा संभव नहीं। हालांकि मंत्री ने मालवा में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि पार्टी ने उन्हें बंगाल चुनाव से दूर रहने कह हिदायत दी है। इसकी वजह, उन्होंने उन पर तीन दर्जन से अधिक फर्जी पुलिस केस बंगाल की ममता सरकार द्वारा दर्ज करवाना बताया है। मंत्री का कथन तो जांच का विषय है, लेकिन बंगाल सरकार की मुखिया ममता बनर्जी की मंत्री से खुन्नस जरूर है। पिछले विधानसभा चुनाव के वक्त ममता बनर्जी अपनी सभाओं में कह चुकी है कि पश्चिम बंगाल में इंदौर का एक भाजपाई ..... (जिसे सुबह सवेरे लिख नहीं सकता), आया है जिसे मैं, चुनाव बाद देख लूंगी। बाद में ममता सरकार ने मंत्री पर एक महिला के जरिए पुलिस केस भी कायम कराया, लेकिन कोर्ट ने मंशा पूरी नहीं होने दी। बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में बंगाल के प्रभारी के तौर पर विजयवर्गीय ने ममता की पार्टी को घुटनों पर ला दिया था। अब इन हालातों के बावजूद भी कद्दावर मंत्री ने बंगाल में पार्टी की ओर से चुनावी ड्यूटी का आग्रह किया था जिसे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने खुफिया जांच एजेंसी की रिपार्ट के बाद नकार दिया। जांच एजेंसी ने मंत्री पर चुनाव के दौरान उनके काफिले पर खतरनाक हमला होने की आशंका व्यक्त की थी। जिसके बाद पार्टी ने सतर्कता बतौर विजयवर्गीय को बंगाल जाने से मना कर दिया।

मोहन का मंत्रालय
आशीष चौधरी

शिवराज का महोत्सव

रायसेन जिले में बीते दिवस संपन्न किसान महोत्सव से राज्य सरकार कुछ नेताओं और विपक्ष दोनों के पेट में दर्द तेज उठ आया। महोत्सव तो काफी हद तक सफल कहा जा रहा है। महोत्सव के उद्घाटन से लेकर समापन तक में किसानों ने काफी रूचि दिखाई और उस पर केंद्रीय मंत्रियों राजनाथ सिंह व नितिन गडकरी की मौजूदगी ने महोत्सव की रौनक बढ़ा दी। देशभर से आए प्रतिनिधियों के 300 से अधिक स्टॉल आकर्षण का केंद्र रहे, पर भाजपा के कुछ प्रदेश स्तरीय नेताओं को महोत्सव के समय और सफलता पर बदहजमी हो रही है। नेताओं का कहना है कि महोत्सव वन मैन शो की तरह रहा और किसान, महोत्सव में शामिल हो कि अपनी उपज मंडी में बेचने जाए? एसे में नेताओं ने महोत्सव को पूरी तरह से राजनीतिक नजरिए से देखा और इसे प्रदेश में 'पांव' और मजबूत करने वाला आयोजन बताया।

ड्रैगन पर उमड़ा प्यार

कल तक जो महाशय सुबह की शाखा में 'स्वदेशी' का संकल्प दिलाते थे और विदेशी सामान देखते ही जिनका खून खौलता था, आजकल उनकी जुबान पर 'चाऊमीन' का स्वाद और चीन का गुणगान है। दरअसल, संघ के एक अनुषांगिक संगठन के ये दिग्गज 'ड्रैगन' के न्योते पर चीन की सैर क्या कर आए, उनका तो हृदय परिवर्तन ही हो गया। भेजा तो गया था यह सोचकर कि वहां जाकर स्वदेशी का झंडा गाड़ेंगे, लेकिन लौटकर आए हैं तो 'चीनी मॉडल' के ऐसे मुरीद हुए हैं कि अब संघ के गलियारों में 'जय-जय चाइना' के ही चर्चे हैं। आलोचक चटकारे लेकर कह रहे हैं कि स्वदेशी का चोला उतारकर शायद अब महाशय 'मेड इन चाइना' वाला तिलक लगाने की तैयारी में हैं।

रायसेन के कृषि महोत्सव में केंद्रीय मंत्री गडकरी बोले

किसान की समृद्धि से ही गांव का विकास

रायसेन (नप्र)। रायसेन के दशहरा मैदान में 11 अप्रैल से चल रहे 3 दिवसीय उन्नत कृषि महोत्सव का सोमवार को समापन हो गया। समापन अवसर पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान रायसेन पहुंचे। उन्होंने प्रदर्शनी का अवलोकन किया।

इस अवसर पर मंच से गडकरी ने कहा कि मुझे बहुत खुशी है, मैं यहां मंत्री के रूप में नहीं आया हूं। मैं किसान के रूप में आया हूं, क्योंकि मैं खेती को देखता हूं, इसका प्रयोग करता हूं।

उन्होंने कहा गांव का विकास तभी होगा जब गांवों के किसानों के हाथों में पैसा होगा। हमारी सरकार ने किसानों के लिए अच्छे-अच्छे योजनाएं बनाई। मोदी के नेतृत्व में गांव, गरीब मजदूर किसानों का कल्याण करना है तभी समृद्ध भारत बनेगा। कृषि महोत्सव में पहुंचे से पहले गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की समीक्षा की।

गडकरी ने की एनएच परियोजनाओं की समीक्षा- दूसरी ओर, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी दोपहर 1 बजे भोपाल से प्रस्थान कर रायसेन के दशहरा मैदान पहुंचे। उन्होंने यहां सबसे पहले राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) परियोजनाओं की समीक्षा की। इसके बाद वे उन्नत कृषि महोत्सव प्रदर्शनी सह प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे।

इस दौरान उनके साथ केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी विशेष रूप से मौजूद रहे और दोनों मंत्रियों ने पहुंचते ही प्रदर्शनी का अवलोकन किया।

इधर, जीतू को पुलिस ने रायसेन पहुंचने से रोका- कार्यक्रम स्थल पर किसानों की समस्याएं बताने जा रहे पीसीसी चीफ जीतू पटवारी को पुलिस ने भोपाल के आनंद नगर में बैरिकेडिंग कर रोक लिया, जिसके बाद पुलिसकर्मियों से बहस कर वे अपने काफिले के साथ वापस लौट गए।पटवारी ने सरकार पर विपक्ष से घबराने का आरोप लगाते हुए कहा है कि मंडियों में किसान 2 हजार रुपए से भी कम में गेहूं बेचने को मजबूर है और कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को उठाती रहेगी।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम-2023 स्वीकृति के लिए प्रस्तुत होना ऐतिहासिक पहल : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

महिला सशक्तिकरण के लिए ऐतिहासिक होगा यह सप्ताह

● प्रधानमंत्री का मुख्यमंत्री ने, अन्नदाताओं को खाद पर सब्सिडी उपलब्ध कराने के लिए माना आभार

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि यह सप्ताह महिला सशक्तिकरण के लिए ऐतिहासिक होगा। संसद का तीन दिवसीय विशेष सत्र 16 अप्रैल को आरंभ हो रहा है, जिसमें महिला आरक्षण के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम-2023 स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि हमारे देश की नारी शक्ति को लोकसभा और विधानसभा में 33त्न स्थान मिलना चाहिए। राज्य सरकार भी 10 अप्रैल से 25 अप्रैल तक 'नारी शक्ति वंदन' पखवाड़ा मना रही है। पूरे प्रदेश में बड़े स्तर पर नारी शक्ति वंदन सम्मेलन होंगे, इसके साथ ही विभिन्न स्थानों पर नारी शक्ति पदयात्रा भी निकल जाएगी। प्रदेश के सभी महाविद्यालयों में इस दौरान नारी शक्ति वंदन से संबंधित कार्यक्रम वृहद स्तर पर आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने यह जानकारी मंत्रि-परिषद की बैठक से पहले अपने संबोधन में दी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वर्ष 2026 को समृद्ध किसान-समृद्ध मध्यप्रदेश की थीम के साथ पूरे प्रदेश में कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इस क्रम में 8 अप्रैल को जबलपुर में आयोजित कृषि मंथन कार्यशाला में देश-विदेश के कृषि वैज्ञानिक, कृषि उत्पादक और एफपीओ शामिल हुए। कार्यशाला में देश के वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिकों के साथ कृषि को एक लाभकारी व्यवसाय के रूप में स्थापित करने, खेत से कारखाने तक उत्पादों की पहुंच सुगम बनाने ,कम पानी में उत्पादन की फसल बढ़ाने और कृषि में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग जैसे विषयों पर सार्थक चर्चा हुई। कार्यशाला मे सहभागी किसानों को कई उपयोगी जानकारियां प्राप्त हुई। कार्यशाला के निष्कर्ष किसानों को उनकी आमदनी बढ़ाने में सहायक सिद्ध होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों एवं कीमतों के रुझानों के बावजूद केन्द्र सरकार किसानों के हित को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। इसके लिये प्रधानमंत्री श्री मोदी का मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आभार माना। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अन्नदाताओं को खाद पर सब्सिडी के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी का आभार मानते हुए कहा कि केन्द्रीय मंत्री मण्डल ने 8 अप्रैल 2026 को फास्फेट एवं पोटेशियम उर्वरको जैसे न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी को मंजूरी दी है।केन्द्रीय मंत्री मण्डल द्वारा खरीफ सीजन 2026 के लिये फास्फेट एवं पोटेशियम उर्वरकों पर पोषण तत्व आधारित सब्सिडी के लिये 41 हजार 833 करोड़ रुपए की बजटीय व्यवस्था को स्वीकृति दी, जो विगत वर्ष से 4,317 करोड़ रूपये अधिक है। खरीफ सीजन 2026 में इससे किसान प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होगे। केन्द्र सरकार उर्वरक निर्माताओं/ आयातकों के माध्यम से किसानों को रियायती दरों पर डीएपी सहित 28 श्रेणियों के फॉस्फेट और पोटेशियम उर्वरक उपलब्ध करा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि रायसेन में 11 अप्रैल से आरंभ तीन दिवसीय उन्नत कृषि महोत्सव का केन्द्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने शुभारंभ किया। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान भी कार्यक्रम में उपस्थित थे। उन्होंने बताया कि इस महोत्सव में उन्नत बीज, सिंचाई तकनीक, कृषि यंत्र, प्राकृतिक खेती, कम्यूनिटी एवं इंटीग्रेटेड फॉर्मिंग एवं कृषि एव बागवानी से संबंधित नई तकनीकों की जानकारी दी जा रही है। लगभग 350 से अधिक स्टॉल लगाये गये हैं और खेती से जुड़े अलग-अलग विषयों पर विभिन्न सत्र आयोजित किये गये हैं। इनमें विभिन्न कृषि वैज्ञानिक, विषय विशेषज्ञ एफपीओ तथा किसान बंधु भाग ले रहे है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि नक्सल उन्मूलन के बाद बालाघाट में अब विकास की गंगा बहेगी। प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के कुशल मार्गदर्शन में प्रदेश में नक्सल गतिविधियों का उन्मूलन हो गया है। अब प्रभावित क्षेत्रों में तेजी से विकास किया जायेगा। आगामी माह बालाघाट में जनजातीय महोत्सव का आयोजन होगा। इसमें सांस्कतिक और खेल गतिविधियों के साथ-साथ विकास से जुड़े हुये सभी विभाग स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप शिविर भी आयोजित किए जाएंगे। धरती आबा अभियान में हितग्राहियों को लाभान्वित करने और मेगा स्वास्थ्य शिविर तथा सिकल सेल स्क्रीनिंग का कार्य भी किया जायेगा साथ ही विभिन्न पारम्परिक व्यंजनों के स्टॉल भी लगाये जाएंगे।

पर्याप्त मात्रा में पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध : खाद्य मंत्री

2904 स्थानों पर हुई जाँच, 4369 गैस सिलेण्डर किये गये जब्त

भोपाल (नप्र)। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्त संरक्षण मंत्री श्री गोविन्द सिंह राजपूत ने बताया कि प्रदेश में आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत एलपीजी की कालाबाजारी रोकने के लिये निरंतर कार्यवाही की जा रही है, अभी तक 2904 स्थानों पर जांच की गई, 4369 एलपीजी सिलेण्डर जब्त किये गए तथा 11 प्रकरणों में एफआईआर दर्ज कराई गई। प्रदेश के 751 रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पंप) की जांच कराई गई है। इसमें 1 प्रकरण में एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई है। प्रदेश के समस्त जिला आपूर्ति नियंत्रक/ अधिकारी एवं ऑयल कंपनी के अधिकारियों को सतत् रूप से पेट्रोल पंपों की जांच करने के निर्देश दिये गये हैं। प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध है। भारत में कच्चे तेल का पर्याप्त भण्डार है, देश एवं प्रदेश की सभी रिफाइनरियां पूरी क्षमता के साथ काम कर रही हैं, जिससे पेट्रोलियम पदार्थों की निरंतर सप्लाई हो सके एवं सप्लाई में कोई रुकावट न आए। मध्यप्रदेश और पूरे देश में एलपीजी पेट्रोल, डीजल, पीएनजी एवं सीएनजी का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। खाद्य मंत्री श्री राजपूत ने भारत सरकार द्वारा निर्धारित 70 प्रतिशत सीमा के अधीन संस्थाओं एवं प्रतिष्ठानों को तय किये गये प्राथमिकता क्रम अनुसार सप्लाई निरंतर जारी रखने के निर्देश दिये हैं। यह भी ध्यान रखा जाये कि सड़क पर कारोबार कर रहे छोटे व्यवसायी (स्ट्रीट वेण्डर) को भी उक्त अनुसार कमर्शियल सिलेण्डर प्रदाय किये जायें। ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सभी प्लांट अतिरिक्त समय तक काम कर रहे हैं। प्रदेश के जिलों में स्थित बॉटलिंग प्लांट तथा वितरकों के पास उपलब्धता एवं प्रदाय की सतत् रूप से समीक्षा की जा रही है।

रसोई गैस की स्थिति

रसोई गैस का प्रदेश के बॉटलिंग प्लांटों में घरेलू एवं कॉमर्शियल एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक बनाए रखा गया है। घरेलू गैस उपभोक्ताओं द्वारा की गई बुकिंग के विरूद्ध एलपीजी सिलेण्डर का प्रदाय निरंतर रूप से किया जा रहा है। साथ ही कॉमर्शियल उपभोक्ताओं को शासन द्वारा तय किये गये प्राथमिकता क्रम अनुसार आवंटन प्रतिशत के आधार पर कमर्शियल गैस सिलेण्डरों की सप्लाई सतत् रूप से की जा रही है। घरेलू एवं कॉमर्शियल की सप्लाई में किसी प्रकार का अवरोध नहीं है। घरेलू एवं कॉमर्शियल सिलेण्डर की सप्लाई एवं वितरण सामान्य है।

पीएनजी गैस

सीजीडी संस्थाओं तथा ऑयल कंपनियों के अधिकारियों के साथ प्रतिदिन समीक्षा बैठक आयोजित की जा रही है। अपर मुख्य सचिव श्रीमती रश्मि अरूण शमी द्वारा विशेष अभियान चलाकर जिन घरों में पाईपलाईन की अधोसंरचना उपलब्ध है, एवं सप्लाई प्राप्तज नहीं कर रहे है, ऐसे 1.5 लाख घरों को आगामी 03 माह में पीएनजी से कनेक्ट करने के लिये निर्देशित किया गया।

'हम भी कभी साहब थे'

82 साल के रिटायर्ड डीएसपी और पत्नी को पन्ना पुलिस ने बनाया क्रिमिनल, भड़के पूर्व अफसर

पन्ना (नप्र)। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पुलिसिंग के मानवीय चेहरे पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। यहां 82 वर्षीय सेवानिवृत्त डीएसपी भरत सिंह चौहान और उनकी बुजुर्ग पत्नी के साथ मदला पुलिस द्वारा कथित दुर्व्यवहार और फिर उन पर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तारी ने पूरे प्रदेश के पूर्व पुलिस अधिकारियों को आक्रोशित कर दिया है। इंदौर से लेकर भोपाल तक अब इस 'वर्दी बनाम वर्दी' की लड़ाई ने तूल पकड़ लिया है।

सीट बेल्ट से शुरू हुआ विवाद- रिटायर्ड राजपत्रित पुलिस अधिकारी संघ के सचिव गिरीश सूबेदार के अनुसार, घटना दो दिन पहले की है जब पूर्व डीएसपी चौहान अपनी पत्नी के साथ पन्ना से ग्वालियर जा रहे थे। रास्ते में मदला थाने के पुलिसकर्मियों ने गाड़ी रोकी। विवाद महज सीट बेल्ट न पहनने को लेकर शुरू हुआ था, लेकिन बात इतनी बढ़ी कि पुलिस ने बुजुर्ग दंपति को हिरासत में ले लिया। आरोप है कि उनके साथ अपराधियों जैसा बर्ताव किया गया और दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक उन्हें थाने में बिठाकर रखा गया।

'बॉडी कैम' वीडियो करेगा फैसला- मामला गर्म होते देख पन्ना की पुलिस अधीक्षक निवेदिता नायडू ने अपना पक्ष रखा है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का हक है, लेकिन पुलिस के पास इस पूरी घटना की रिकॉर्डिंग है। ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मियों के बॉडी-वियर कैमरे में सब कुछ कैद है और जनता वीडियो देखकर खुद आकलन कर सकती है कि गलती किसकी थी।

गिरीश सूबेदार, सचिव, सेवानिवृत्त राजपत्रित पुलिस अधिकारी संघ ने कहा एक वरिष्ठ अधिकारी जिन्होंने अपनी पूरी उम्र विभाग को दी, उनके और उनकी पत्नी के साथ महज एक ट्रैफिक विवाद में ऐसा सलूक निंदनीय है। हम इस अपमान के खिलाफ चुप नहीं बैठेंगे।

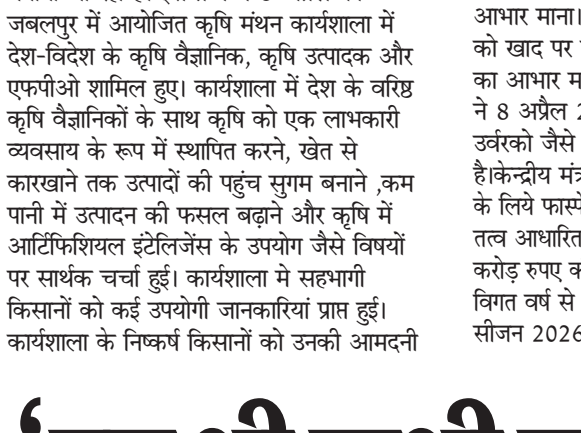

क्यों भड़के पूर्व पुलिस अफसर?

पूर्व अधिकारियों का कहना है कि एक 82 साल के बुजुर्ग और उनकी पत्नी पर आर्म्स एक्ट जैसी धाराएं लगाना पुलिस की अति को दर्शाता है। क्या एक पूर्व राजपत्रित अधिकारी के साथ सड़क पर ऐसा व्यवहार किया जाना चाहिए? इसी सवाल को लेकर सोमवार को प्रदेशभर के लगभग तीन दर्जन सेवानिवृत्त अधिकारी इंदौर में ज्ञापन सौंपकर डीजीपी से पन्ना पुलिस के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करेंगे।

गुना में कार-ट्रैक्टर और दो बाइकों की भिड़ंत में पति-पत्नी की मौत

ओवरटेक के चक्कर में उजड़ गया परिवार

गुना (नप्र)। जिले के कुंभराज-मोहनपुर मार्ग पर रविवार सुबह एक दर्दनाक सडक़ हादसा सामने आया है, जिसमें एक कार, ट्रैक्टर और दो बाइकों के बीच हुई जबरदस्त भिड़ंत में पति-पत्नी की जान चली गई। हादसे के दौरान मौके पर चीख-पुकार मच गई। इस दुर्घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है, जबकि एक 4 वर्षीय बालक को मामूली चोटें आई हैं।

ओवरटेक के प्रयास में हुई टक्कर- हादसा सुबह करीब 10 बजे सिंगल रोड पर हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, एक कार चालक आगे चल रहे ट्रैक्टर को ओवरटेक करने का प्रयास कर रहा था। इसी दौरान मोड़ पर ट्रैक्टर-ट्रॉली के लहराने से कार उससे टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का टायर फट गया और वह अनियंत्रित हो गई। इसी बीच सामने से आ रही दो मोटर साइकिलें भी इस दुर्घटना की चपेट में आकर ट्रैक्टर और कार से जा भिड़ी।

बुजुर्ग दंपति ने मौके पर तोड़ा दम

दुर्घटना में एक बाइक पर सवार बड़ौद गांव निवासी कैलाश सिंह (58) और उनकी पत्नी बदी बाई (55) की मौके पर ही मौत हो गई। बाइक पर उनके साथ उनका 4 साल का नाती आशीष भी सवार था। गनीमत रही कि मासूम को गंभीर चोटें नहीं आईं और प्राथमिक उपचार के बाद उसकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है। वहीं, दूसरी बाइक पर सवार एक अन्य युवक को गंभीर चोटें आने के कारण प्राथमिक उपचार के बाद गुना जिला अस्पताल रेफर किया गया है।

थाना प्रभारी,पंकज त्यागी, कुंभराज ने बताया प्रथम दृष्टया यह मामला तेज रफ्तार और सिंगल रोड पर गलत तरीके से ओवरटेकिंग का लग रहा है। कार चालक के बयान लिए जा रहे हैं और वाहनों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई है। दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी।

पटवारी की पाठशाला में होगा 'रिजल्ट' का हिसाब

कांग्रेस के फिसड्डी जिला अध्यक्षों की छुट्टी की तैयारी

भोपाल (नप्र)। मध्य प्रदेश में करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस अब मजबूत संगठन के कागजी दावों से बाहर निकलकर जमीनी हकीकत का सामना करने जा रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के एक साल पूरे होने पर उनके कामकाज के पोस्टमार्टम की तैयारी कर ली है। 15 से 18 अप्रैल तक चलने वाली इस मैराथन बैठक में उन चेहरों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, जो पिछले एक साल में केवल सोशल मीडिया पर ही सक्रिय रहे।

रवींद्र भवन में ब्लॉक अध्यक्षों की क्लास- इस अभियान का सबसे अहम हिस्सा 17 अप्रैल को भोपाल के रवींद्र भवन में होने वाला ब्लॉक अध्यक्षों का सम्मेलन है। पहली बार कांग्रेस जिला अध्यक्षों से आगे बढ़कर सीधे ब्लॉक स्तर के सेनापतियों से संवाद करेगी। इस बैठक में सांसद, विधायक और जिला प्रभारियों की मौजूदगी में आगामी चुनावों की रणनीति तय होगी।

भारत के संविधान निर्माता, भारत रत्न

डॉ. भीमराव अम्बेडकर

को

कोटि-कोटि नमन

न्याय, समानता और
समरसता के मूल्यों से
सशक्त होता मध्यप्रदेश

136वीं जयंती समारोह

14 अप्रैल, 2026
डॉ. अम्बेडकर नगर (महू)
जिला इंदौर

मुख्य अतिथि

डॉ. मोहन यादव

मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश

"भारत रत्न डॉ. भीमराव अम्बेडकर के समाज कल्याण के लिए किए गए योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता बाबासाहेब की न्याय, समानता और समरसता की विरासत हमें हमेशा प्रेरित करती रहेगी।"

-डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री

डॉ. भीमराव अम्बेडकर के सपनों को समर्पित विकास

आस्था से जुड़ाव

बाबासाहेब से जुड़े महू, दिल्ली, नागपुर, मुंबई और लंदन में स्थित 5 ऐतिहासिक स्थल मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में शामिल

वैश्विक आस्था और अध्ययन का केंद्र महू

स्मारक, संग्रहालय, सभागार, स्वागत द्वार एवं अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च सेंटर का विकास

सम्मान का प्रतीक नामकरण

महू रेलवे स्टेशन का नाम 'डॉ. अम्बेडकर नगर'

युवा स्व-रोज़गार उद्यम को नई उड़ान

डेयरी इकाई के लिए कामधेनु योजना में ₹42 लाख तक ऋण

आर्थिक कल्याण योजना में ₹1 लाख तक अनुदान

संत रविदास स्व-रोज़गार योजना में ₹1 लाख से ₹50 लाख तक सहायता

उद्योग उदय योजना के माध्यम से MSME को वित्तीय सहयोग

शिक्षा में उत्कृष्टता का सम्मान

डॉ. भीमराव अम्बेडकर मेधावी विद्यार्थी पुरस्कार योजना 10वीं-12वीं में प्रोत्साहन पुरस्कार

उच्च शिक्षा एवं अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन हेतु अम्बेडकर फैलोशिप

पर्यावरण और विरासत का संगम

सागर में 25वां डॉ. बी.आर. अम्बेडकर वन्यजीव अभयारण्य घोषित

D-11005/26

सीधा प्रसारण @Cmmadhyapradesh @jansampark.madhyapradesh @Cmmadhyapradesh @jansamparkMP JansamparkMP

डॉ. मोहन यादव का अभ्युदय मध्यप्रदेश